● वर्ष-4
● अंक-12
रायपुर, शनिवार
24 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

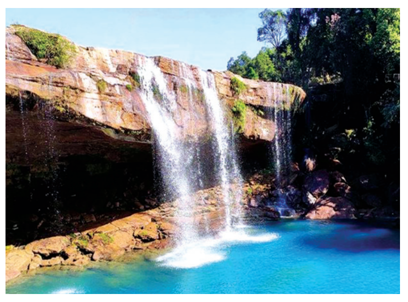

पेज-6›› मेघालय राज्य की खूबसूरती देखेंगे...

भारत-यूक्रेन ने जारी किया ज्वाइंट स्टेटमेंट

मानवीय मदद से लेकर दवा तक हुए 4 समझौते

नई दिल्ली। भारत के प्रधान मंत्री की यूक्रेन यात्रा पर भारत-यूक्रेन संयुक्त वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की। प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता के सम्मान जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में आगे सहयोग के लिए अपनी तत्परता दोहराई। वे इस संबंध में करीबी द्विपक्षीय बातचीत की वांछनीयता पर सहमत हुए। भारतीय पक्ष ने अपनी सैद्धांतिक स्थिति दोहराई और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके एक भाग के रूप में भारत ने जून 2024 में स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

जेलेंस्की से मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब युद्ध के शुरुआती दिन थे तो आपने भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने में मदद की। संकट के इस समय में आपकी मदद के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं... दुनिया यह अच्छी तरह से जानती है कि इस दौरान युद्ध में हमने दो भूमिकाएँ निभाई...पहली भूमिका थी मानवीय दृष्टिकोण की...मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से चाहे जो भी आवश्यकता हो, भारत हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और दो कदम आगे रहेगा। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत ने युद्ध में कभी भी तटस्थ रुख नहीं अपनाया है, बल्कि वह हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। पीएम मोदी ने संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति की वकालत करने के भारत के लगातार प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत इस युद्ध में कभी भी तटस्थ नहीं था, हम शांति के पक्ष में हैं।

मोदी के पुतिन-जेलेंस्की को गले लगाने के सवाल पर बोले विदेश मंत्री, कहा- यह भारत की संस्कृति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत की संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने हमेशा हर स्थान पर हर नेता को गले लगाया है। दरअसल पिछली बार रूस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था। इसकी आलोचना भी हुई थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को गले लगाया। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो गले लगाते हैं। कीव में भी मैनें यही देखा। प्रधानमंत्री ने पहले भी अन्य नेताओं को मुलाकात के दौरान गले लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और जेलेंस्की ने अंतर-सरकारी आयोग को विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का जिम्मा सौंपा। जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुख्य चर्चा यूक्रेन के युद्ध पर थी।

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में किया 13 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश

नई दिल्ली। अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार हो रहा भारत का निवेश अच्छी खबर लेकर आया है। वैश्विक फर्म नोवा स्पेस ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते एक दशक में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 13 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। इससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में करीब चार गुना से ज्यादा 60 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव नामक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि भारत फंडिंग के मामले में दुनिया का आठवां सबसे बड़ा अंतरिक्ष राष्ट्र है। इस क्षेत्र में तेजी से स्टार्ट अप विकसित हुए हैं। नोवा स्पेस के कार्यकारी सलाहकार स्टीव बोचिंगर ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र ने पिछले एक दशक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद में 60 अरब डॉलर का योगदान दिया है। इससे 47 लाख नौकरियां सृजित हुईं। साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 96,000 लोगों को सीधे रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि इसरो ने नोवास्पेस को अंतरिक्ष अभियानों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर एक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। बोचिंगर ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुमानित राजस्व 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2023 में बढ़कर 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। उन्होंने कहा कि भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न प्रत्येक डॉलर अप्रत्यक्ष और प्रेरित लाभ के बाद 2.54 अमेरिकी डॉलर में बदल जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसरो रोजाना आठ लाख मछुआरों की मदद करता है। साथ ही 1.4 अरब भारतीयों को उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमानों का लाभ देता है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) को चालू करना और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है। अगले साल लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की वैज्ञानिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए पहला कदम होगा।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने कहा कि केंद्र ने स्टार्ट-अप के लिए एक सीड फंड योजना शुरू की है। साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र के उद्यमियों के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ एक डिजाइन लैब की स्थापना भी की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए 1,000 करोड़ रुपये के बजट का एलान किया है.

केंद्रीय गृह मंत्री शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, केंद्रीय आवास एवम शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू सहित छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद के सदस्यगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं

शाह का कांग्रेस पर निशाना, राहुल से पूछे सवाल

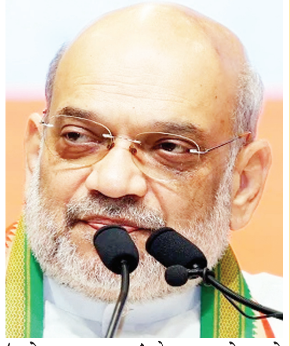

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर सख्त हो गए और ग्रैंड ओल्ड पार्टी के फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के बाद धारा 370, 35ए, दलित आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह ने लिखा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के बाद दलितों, जनजातियों, पहाड़ियों और पिछड़े समुदायों को आरक्षण देकर उनके खिलाफ वर्षों के भेदभाव को समाप्त कर दिया।

भाजपा नेता ने लिखा कि सत्ता के लालच को पूरा करने के लिए देश की एकता और सुरक्षा को बार-बार खतरे में डालने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके एक बार फिर अपने गुप्त इरादों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में किए गए वादों को देखते हुए, यहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं।

क्या कांग्रेस 'नेशनल कांफ्रेंस' के जम्मू-कश्मीर में फिर से 'अलग झंडे' के वादे का समर्थन करती है?

क्या राहुल गाँधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के छ्द्महष्ट के निर्णय का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गाँधी, पाकिस्तान के साथ 'स्पष्ट ट्रेड' शुरू करने के नेशनल कांफ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं?

क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है?

इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरासामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है?

क्या कांग्रेस चाहती है कि 'शंकराचार्य पर्वत' 'तख्त-ए-सुलिमान' और 'हरि पर्वत' 'कोह-ए-मारन' के नाम से जाने जाएँ? क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौपने का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस पार्टी छ्द्महष्ट के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?

प्रमुख समाचार

नेपालः बस नदी में गिरी, 24 की मौत

गोरखपुर। गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई एक भारतीय बस शुक्रवार को पोखरा से

काठमांडो जाने के दौरान नेपाल तनहुन के अबुखैरेनी में मार्स्यांगडी नदी में गिर गई। जिसमें बस चालक समेत 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हैं। सूचना के बाद सीमावर्ती जिला महराजगंज के नौतनवा तहसील के एसडीएम और सोनौली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घटना सोनौली सीमा से करीब 170 किमी दूर मस्यागड़ी नदी में घटी है। तनाहुन के एसपी वीरेंद्र शाही ने बताया कि मार्सयांगडी अंबुखैरेनी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड नंबर दो स्थित ऐन पहरा के पास नदी में बस गिर गई। स्थानीय पुलिस कार्यालय के निरीक्षक अबू खैरेनी मौके पर पहुंच गए हैं। नेपाल में यात्रियों को ले जा रही बस के नदी में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी में बस के नदी में गिरने से 24 भारतीयों की मौत हो गई। इस बस में कुल 42 यात्री सवार थे। राजधानी काठमांडो में अपने गंतव्य से लगभग 110 किलोमीटर दूर तनहुन जिले में मार्सयांगडी नदी में गिर गई.

शिवराज ने पिछड़े वर्गों के लिए किये गये प्रयासों को लेकर तारीफ की

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किये गये प्रयासों को लेकर शुक्रवार को नरेन्द्र मोदी सरकार की तारीफ की तथा कांग्रेस नीत विपक्ष पर इस वर्ग के वास्ते महज 'जुबानी जमाखर्च' करने का आरोप लगाया। कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री चौहान स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल की स्मृति में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंडल को तीन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इन अधिकारियों को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गयी पुलिस गोलीबारी के लिए जिम्मेदार समझा गया था।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंडल 'धानुक' थे और धानुक एक पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) है जिसे ''मेरे राज्य एवं बिहार में राष्ट्रनिर्माण में योगदान के लिए जाना जाता है।'' उन्होंने कहा, ''हमारे विरोधी पिछड़े वर्गों के नाम पर केवल दिखावा करते हैं जबकि वर्तमान भाजपा

महाराष्ट्र बंद को एमवीए गठबंधन ने वापस लिया

मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले को लेकर बुलाए गए बंद को अब वापस ले लिया गया है। मामले में विपक्षी पार्टियों ने कल 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। हालांकि, अब इसे वापस ले लिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शरद पवार ने अपील करते हुए कहा था कि संविधान का सम्मान करते हुए कल का बंद खत्म करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बंद इसलिए बुलाया गया है ताकि सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर हो। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बंद बुलाने वालों पर सख्ती बरतने को कहा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। इसका मतलब है कि एमवीए और अन्य राजनीतिक दल शनिवार को महाराष्ट्र में कोई बंद नहीं कर सकते। शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद के बारे में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बॉम्बे एचसी पीठ ने कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को उनके महाराष्ट्र बंद के साथ आगे बढ़ने से रोक देगी।

राजनीति में अपना सफर शुरु करने को तैयार महबूबा की बेटी

जम्मू। विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू-कश्मीर में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। जिसको लेकर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस चुनाव में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी परिवार की घरेलू सीट से चुनावी शुरुआत के लिए तैयार हैं। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अनंतनाग के बिजबेहरा निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिख रही हैं। राज्य की बिजबेहारा विधानसभा सीट मुफ्ती परिवार की घरेलू सीट है और ये उनका गढ़ भी माना जाता रहा है। साल 1996 में महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के टिकट पर यह विधानसभा सीट जीती थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और साल 1999 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। उनके पहले इल्तिजा के दादा और महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी 1967 में बिजबेहरा से चुनाव जीता था। इस तरह इल्तिजा इस सीट से चुनाव लड़ने वाली अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सदस्य होंगी।

क्या जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा वापस लाएगी कांग्रेस

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी आज कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता का लालच कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक साथ ले आया है। उन्होंनेकहा कि आज गृह मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल किये हैं। नेशनल कांफ्रेंस की ये घोषणा है कि वह जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा वापस लाकर राष्ट्र भर में अशांति का माहौल लाने का दुस्साहस करेगी। स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉफ्रेंस के इशारे पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी रुख को उजागर कर दिया है। क्या कांग्रेस जेकेएनसी के दलितों, गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण समाप्त करने के वादे का समर्थन करती है, जिससे उन पर अन्याय हो रहा है? उन्होंने कहा कि धारा-370 हटने के बाद भारत ने और भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक निशान, एक विधान और एक प्रधान रहेगा।

बढ़ते कदम

दुनिया की भूख मिटाने को तैयार भारत, लेकिन खाद्य सुरक्षा अब भी वैश्विक चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत खाद्यान्न अधिशेष वाला देश बन गया है और वह वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 65 वर्ष पूर्व जब यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था, उस समय भारत की खाद्य सुरक्षा विश्व के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन अब वैश्विक खाद्य संकट की चुनौतियों के बीच भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों को खाद्य पदार्थों के निर्यातक देश के रूप में रेखांकित हो रहा है। साथ ही कोरोना काल से लगातार 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में अनाज देने की भारत की पहल दुनिया भर में रेखांकित हो रही है। वर्ष 2023 में भारत ने करीब 50 अरब डॉलर मूल्य का कृषि निर्यात किया है और दुनिया का आठवां बड़ा कृषि निर्यातक देश बन गया है।

इन दिनों वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रकाशित हो रहीं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत की नई अहमियत पता चल रही है। इस समय जब रूस-यूक्रेन युद्ध, इस्राइल-हमास युद्ध और अन्य भू-राजनीतिक कारणों से वैश्विक खाद्य संकट गहराता जा रहा है, तब दुनिया के अनेक देशों को

खाद्य संकट से निपटने और उनकी खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर भारत एक मददगार देश बना हुआ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि कृषि व्यवस्था को बदलना समय की मांग है। देश के किसान भारत को विश्व की ऑर्गेनिक फूड बास्केट बना सकते हैं और विश्व के देशों के लिए भारत मददगार हो सकता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष सहित सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न वैश्विक संगठनों द्वारा भारत की खाद्य सुरक्षा की सराहना की जा रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश ने कृषि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। खासतौर से पिछले 10 वर्षों में कृषि विकास के अभूतपूर्व प्रयासों से अब भारत दुनिया के खाद्य कटोरे के रूप में पहचान बना रहा है। कृषि भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। भारतीय कृषि में 90 प्रतिशत किसानों के पास बहुत कम जमीन है और ये छोटे किसान भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं। कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए फसलों की 1,900 नई जलवायु-अनुकूल किस्में उपलब्ध कराई गई हैं। भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने मोटे अनाज को श्रीअन्न का नाम देकर इसे एक लाभदायक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित नौ उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र भी शामिल है। बजट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए बजट में सरकार उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख फसलों का, जो तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, उसके मुताबिक कुल खाद्यान्न उत्पादन 3288.52 लाख टन अनुमानित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया में दूध, दालों और मसालों का नंबर एक उत्पादक है। इसके अलावा, देश खाद्यान्न, फल, सब्जियां, कपास, चीनी और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ऐसे में जब देश में खाद्यान्न उत्पादन ऊंचाई बना रहा है, तब खाद्यान्न भंडारण की अधिक क्षमता भी जरूरी है। अभी 12 से 14 फीसदी तक अन्न बर्बाद हो जाता है। देश में भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन की है, उसे 2,150 लाख टन किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ती हुई वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षा जरूरतों के बीच देश में सरकार के द्वारा अधिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रणाली मॉडल पर केंद्रित जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, हरित और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वित्तपोषण, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए अधिक निवेश, समावेशी कृषि मूल्य शृंखलाएं, कृषि-खाद्य क्षेत्र को बदलने के लिए नई-उभरती डिजिटल तकनीकों की, भूमि के डिजिटलीकरण के लिए खेती में ड्रोन को बढ़ावा, कृषि अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत साझेदारी और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों की डगर पर आगे बढ़ने की कारगर रणनीति अपनाई जाएगी।

कोरबा में एक साथ मिले स्वाइन फ्लू के पांच नए मरीज

कोरबा। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अब तक 15 दिनों में छह लोगों की मौत की बात सामने आई है। इसी तरह कोरबा जिले में भी स्वाइन फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरु कर दिए हैं। जिले में हाल ही में स्वाइन फ्लू के पांच नए एक्टिव मरीज पाए गए हैं। सभी का उपचार किया जा रहा है।

नए मरीज सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में इस बीमारी से पीड़ित पांच नए मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड़ पर है।

मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसे मरीजों के लिए अलग से आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 20 बिस्तर वाले अलग से बेड तैयार किए गए हैं। वह इसके अलावा अलग से टीम भी बनाई गई है जो लगातार ऐसे मरीजों की निगरानी करते रहेंगे।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केसरी ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य अमले ने लोगों को सचेत रहने को कहा है। विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण सामने आते हैं, तो तत्काल उसकी जांच कराए और अस्पताल में उपचार लाभ लें।

स्वाइन फ्लू एक वायरल इंफेक्शन है, जो मूल रूप से सूअरों से मनुष्यों में फैला। स्वाइन फ्लू एच1एन1 इन्फ्लूएंजा एक तरह का वायरस है। यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। नियमित इन्फ्लूएंजा और स्वाइन फ्लू के लक्षण बहुत मिलते-जुलते हैं। गर्मी और मानसून के मौसम में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए कई वैक्सीन हैं, साथ ही इलाज के लिए कई तरह के एंटीवायरल उपचार भी मौजूद हैं। इसके अलावा हाइजीन का ख्याल रखकर और सर्जिकल मास्क पहनकर स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है।

स्वाइन फ्लू के लक्षण?

बुखार आना, सिरदर्द होना, डायरिया होना, खांसी आना, छींक आना, ठंड लगना, गले में खराश होना, थकान, नासिका मार्ग ब्लॉक होना।

किन लोगों को स्वाइन फ्लू का खतरा ज्यादा

अध्ययनों के मुताबिक कुछ लोगों में स्वाइन फ्लू का खतरा अन्य की तुलना में ज्यादा होता है। इनमें शामिल हैं, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग के मरीज, डायबिटीज के मरीज, रेस्पिरेटरी समस्याएं जैसे निमोनिया से ग्रसित लोग, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 2 साल से छोटे बच्चे को स्वाइन फ्लू जल्द होने की संभावना रहती है।

स्वाइन फ्लू से बचाव

खांसते और छींकते समय मुंह पर रूमाल रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। भरपूर मात्रा में स्वच्छ पानी पीएं और पौष्टिक आहार का सेवन करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क पहनें और हाथों को अच्छे से साफ करें। मरीजों से मिलते समय दूरी का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

मलेरिया और उल्टी दस्त के बढ़ते प्रकोप पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

बिलासपुर। बिलासपुर और बस्तर में मलेरिया एवं रतनपुर क्षेत्र में उल्टी दस्त से मौत के साथ ही संक्रमण फैलने को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इस मामले के लिए अलग बेंच निर्धारित की जा रही है, जिसमें सुनवाई होगी।

बता दें, कि जून का महीना मलेरिया माह घोषित होने के बावजूद शासन की ओर से बचाव के लिए कोई अभियान नहीं चलाने तथा बस्तर के बीजापुर आश्रम में रह रहे दो मासूम बच्चों की मौत, बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में तेजी से मलेरिया फैलने व रतनपुर क्षेत्र में उल्टी दस्त के प्रकोप को लेकर मीडिया की खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है।

पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव शिक्षा, सचिव स्वास्थ्य, बिलासपुर कलेक्टर, बीजापुर कलेक्टर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य संचालक, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सहित 11 लोगों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।

धमतरी में कांग्रेस की विधायक को खुद के सुरक्षा की चिंता

धमतरी। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक ने सरकार से खास डिमांड की है। विधायक अम्बिका मरकाम ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। विधायक का कहना है कि उन्हें परमानेंट सुरक्षा बल दिया जाए। क्योंकि वो लगातार संवेदनशील इलाकों का भ्रमण करती रहती हैं। इसके लिए उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है। सुरक्षा को लेकर विधायक ने गृह मंत्री विजय शर्मा से भी मुलाकात की है।

सिहावा विधायक अम्बिका मरकाम की मांग है कि उन्हें 1 से 4 सुरक्षा जवानों का बल परमानेंट दिया जाए। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायकों को सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन नक्सल प्रभावित विधायक होने के कारण उनके पास सुरक्षा व्यवस्था कम है। फिलहाल सरकार की ओर से उन्हें 3 पीएसओ दिए गए हैं, लेकिन उन्हें इतनी सुरक्षा कम लगती है। विधायक ने सिहावा को नक्सल प्रभावित इलाका बता कर 1- 4 के बल की सुरक्षा की मांग की है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में दौरे के लिए उन्हें जिला पुलिस पूरी सुरक्षा देती है, फिर भी महिला विधायक को लगता है कि इन्हें ज्यादा बल और फॉलो गार्ड दिया जाना चाहिए।

विधायक अम्बिका मरकाम ने कहा मैं लगातार पत्र के जरिए सरकार से मांग कर रही हूं कि मुझे एक-चार का सुरक्षा बल परमानेंट दिया जाए। उनके फॉलो को बढ़ाया जाए। हालांकि पुलिस की सुरक्षा दौरे के दौरान मुझे दी जाती है, लेकिन परमानेंट सुरक्षा की मैं मांग कर रही हूं। मैंने इसे लेकर कई बार पत्र भी लिखा है। हालांकि अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। बता दें कि अम्बिका मरकाम कांग्रेस की ओर से जीतकर सिहावा विधानसभा की विधायक चुनी गई हैं। सिहावा विधानसभा संवेदनशील क्षेत्र है। यहां नक्सलियों का दबदबा है। यही कारण है कि विधायक को खुद के सुरक्षा की फिक्र हो रही है। हालांकि दौरे के दौरान विधायक को जिला पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा दी जाती है।

कचरे पर विवाद, ग्राम पंचायत ने चार घंटे निगम कर्मचारियों को रोका

गौरेला पेंड्रा मरवाही। नगर पालिका गौरेला और ग्राम पंचायत भदौरा के बीच शुक्रवार को कचरा फेंकने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भदौरा गांव के ग्रामीणों ने लगभग चार घंटे कचरा फेंकने के दो वाहनों को कर्मचारियों सहित मौके पर ही रोक लिए। वहीं विवाद निपटाने के लिए जनपद सीईओ और नगर पालिका सीएमओ को मौके पर आना पड़ा। काफी लंबी चर्चा के बाद कचरा वापस उठाने की शर्त पर मामला शांत हुआ।

नगरी निकाय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के युक्ति युक्त निपटानारा एक बड़ी समस्या हो गई है और यह समस्या अब विवाद का रूप ले रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के भदौरा ग्राम पंचायत में जहां आज सुबह आठ बजे नगरीय निकाय गौरेला का दो वाहन कचरा डंप करने आया। जिसमें एक ट्रैक्टर व एक छोटा हाथी था।

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कचरा फेंकने आये दोनों वाहनों को कर्मचारियों समेत मौके पर ही रोक लिया। ग्रामीणों के पहुंचने से पूर्व ट्रैक्टर ने कचरा डंप कर दिया था। जबकि दूसरे वाहन में कचरा लोड था। ग्रामीणों ने कर्मचारियों से पूछा कि किसकी इजाजत और सहमति से आप ग्राम पंचायत क्षेत्र में कचरा डंप कर रहे हैं। जिस पर कर्मचारियों ने सीएमओ का नाम बता दिया।

मौके से ग्रामीणों ने सीएमओ से नगर पालिका गौरेला से बात की तो उन्होंने भी स्तब्ध से शासकीय जमीन पर कचरा डंप करने की बात कही। जिस पर ग्रामीण भड़क गए और मौके पर सरपंच सहित अन्य ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्रामीणों ने सीएमओ को मौके पर बुलाने की मांग शुरू कर दी।

सीएमओ मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। जिसके बाद जनपद पंचायत गौरेला के सीईओ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करने की कोशिश की। ग्रामीण टस से मस नहीं हुए। फिर लगभग एक बजे नगर पंचायत गौरेला के सीएमओ मौके पर पहुंचे। जहां ग्रामीणों ने उन पर अपनी भड़ास उतारी और ग्राम पंचायत क्षेत्र में बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के कचरा डंप करने को लेकर जमकर खरी खोटी भी सुनाई।

8-8 लाख के 2 हार्डकोर ईनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। सुकमा पुलिस के सामने 8-8 लाख रूपए के दो ईनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें मड़कम मुया पिता स्व। सुक्का (पीएलजीए बटालियन नं। 01 कम्पनी नंबर 02 प्लाटून नंबर 02 सेक्शन "बी" का पार्टी सदस्य, ईनामी 08 लाख रूपये) उम्र लगभग 22 वर्ष जाति मुरिया निवासी एलाड़मड़गू थाना भेज्जी जिला सुकमा और मड़कम सन्ना पिता स्व। सोना (पीएलजीए बटालियन नंबर 01, कंपनी नंबर 01, प्लाटून नंबर 03 सेक्शन "बी" का पार्टी सदस्य/पीपीसीएम ईनामी 08 लाख रूपये) उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी दुरनदरभा, कुरसम पारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन की "छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति" एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे "नियद नेल्ला नार" योजना से प्रभावित होकर तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने पर पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के उद्देश्य से इन्होंने समर्पण किया है।

पुलिस के मुताबिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में नीरज कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी 219 वाहिनी सीआरपीएफ, परमेश्वर तिलकवार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुकमा एवं निरीक्षक शिवानंद तिवारी थाना प्रभारी सुकमा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया।

ग्रामीणों ने चंदा कर चिनार नदी पर बनाया लकड़ी का अस्थायी पुल

कांकेर। जिले के सुदूरवर्ती गांव में आज भी लोग लकड़ी के पुल बनाकर अपना रास्ता खुद बनाने को मजबूर हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के सुदूरवर्ती गांव बासकुंड पंचायत के आश्रित गांव ऊपर तोनका, नीचे तोनका, चलाचूर की, जहां ग्रामीण कई वर्षों से चिनार नदी में पुल बनाने की आस लगाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को शासन प्रशासन ना जनप्रतिनिधि किसी ने अब तक नहीं सुनी।

ग्रामीणों ने बताया कि चिनार नदी पार करने के बाद 3 गांव ऊपर तोनका, नीचे तोनका और चलाचूर के ग्रामीणों को बारिश के महीनों में नदी पार करने के लिए हर साल लकड़ी का पुल बनाना पड़ता है। लकड़ी के पुल के सहारे ग्रामीणों को आने जाने की सुविधा होती है। ग्रामीण कई बार पुल निर्माण कराने नेता व अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं पर यहां अब तक पुल नहीं बन पाया है।

ग्रामीण लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे। 2 वर्ष पहले इन गांवों तक पहुंचने पक्की सड़क तो बन गई है पर चिनार नदी पर पुल नहीं बन पाया। ऐसे में ग्रामीणों ने एकजुट होकर चंदा करके श्रमदान कर लकड़ी का पुल बनाया है, जिससे लोग आना जाना कर रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को इस पुल के बन जाने से अब राहत है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उफनते नदी को पार करते वक्त हादसे का डर खत्म हो चुका है, लेकिन हादसा बताकर नहीं आती है। लकड़ी का पुल आखिर कब तक साथ देगा। बहरहाल अभी तो ग्रामीणों ने अपने आने जाने के लिए बांसबल्ली का जुगाड़ कर यह पुल बना लिया है, लेकिन इस नदी में पुल कब बनेगा, जिसका इंतजार करते ग्रामीण थक चुके हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

छात्र संघ चुनाव की उठी मांग कोरबा में छात्रों ने उठाई आवाज

कोरबा। छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर से हवा तेज होने लगी है। अभाविप ने छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अभाविप ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पूर्व में लगातार प्रतिवर्ष छात्रसंघ चुनाव किए जाने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तथा विकास युवा नेतृत्व के माध्यम से संपन्न होता था। लेकिन 2016 के पश्चात प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। पिछले दो सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। अभाविप कांकेर जिला के जिला संयोजक आदित्य मिश्रा ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से छात्रों के नेतृत्व क्षमता में विकास के साथ छात्रहित में कार्य होने लगते हैं। प्रदेश सरकार छात्रहित को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रदेश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से छात्रसंघ चुनाव करवाये और जल्द से जल्द छात्रसंघ चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएं।

दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख की ठगी

दुर्ग। जिले में इन दिनों शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच एक दिन पहले बीएसपी कर्मचारी से 11 लाख की ठगी की गई थी। वहीं, अब दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक से 15 लाख की ठगी की गई। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। यहां के साकेत कॉलोनी निवासी एक युवक ने शेयर ट्रेडिंग टिप्स के चक्कर में अपने 15 लाख रुपए गवां दिए। ठगों ने ऐसा जाल बुना था कि वह उसमें फंसता ही चला गया। फिलहाल, इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मोहन नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साकेत कॉलोनी दुर्ग निवासी सौरभ स्वर्णकार ने ऑनलाइन विज्ञापन देखने के बाद शेयर ट्रेडिंग के लिए टेलीग्राम एप के जरिए कुछ लोगों से संपर्क किया। 19 दिसंबर को उससे एक लिंक के जरिए एप डाउनलोड करवाया गया। उसकी केवाईसी के लिए आधार और पैन कार्ड की फोटो भी अपलोड करवाई गई। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया।

भारत बंद के दौरान जबरदस्ती कराया बंद, एफआईआर दर्ज

सूरजपुर। एसटी-एससी आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को 'भारत बंद' का आह्वान किया था। इस दौरान सूरजपुर में प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को जबरन बंद कराए और एनएच 43 मार्ग को जाम कर दिया था। इस मामले में अब कोतवाली पुलिस ने 15 लोगो से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल, दलित और आदिवासी संगठनों (एसटी-एससी वर्ग) ने गर्त पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का ऐलान किया था। इस दौरान पूरे देश में प्रदर्शनकारियों ने हो-हल्ला मचाया। तो वहीं सूरजपुर जिला मुख्यालय में नेशनल हाईवे 43 पर चक्काजाम किया गया और साथ ही दुकानों को जबरन बंद कराया गया। इसे लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में कोतवाली सूरजपुर थाना प्रभारी विमलेश दुबे ने बताया कि 15 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

दर्दनाक हादसा : निर्माणाधीन पुल का गिरा छज्जा

भानुप्रतापपुर। प्रदेश के कांकेर जिले के अंतर्गत भानुप्रतापपुर में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। ग्राम पंचायत चारगांव के निर्माणाधीन पुल का छज्जा गिरने से 1 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हैं, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को तत्काल अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान हेमंत दुग्गा, लकानार का निवासी के रूप में हुई। गुरुवार की रात अचानक शुरू हुई भारी बारिश से बचने के लिये 3 युवक चारगांव में नदी पर बन रहे पुल के नीचे जा कर खड़े थे। इसी दौरान बारिश के चलते निर्माणाधीन पुल का प्लास्टर उनपर गिर गया और तीनों युवक इसके नीचे दब गए। इस घटना में हेमंत दुग्गा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोगों को गंभीर चोट आई है। इस मामले में सिकसोड थाना क्षेत्र के एसडीओपी अमर सिदार ने घटना की पुष्टि की है और कहा कि मामले की जांच जारी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने युवक को पहुंचाया अस्पताल

कोरबा। पाली थाना अंतर्गत एनएच मुख्य मार्ग पाली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया। बाइक सवार खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का काफिला सड़क से गुजर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने घायल युवक की स्थिति को देख काफिला रुकवाया और 112 को सूचना दी। उन्होंने स्वयं अस्पताल जाकर घायल युवक को वहां पहुंचाया। इलाज के बावजूद युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राम अवतार जगत पोलमी के रूप में की गई है, जो पाली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में लिपिक के पद पर काम करता था। बुधवार को किसान ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह अपनी बेटी को लेने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मृतक को अस्पताल पहुंचाने के बाद भी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार को टोल नाका के पास पकड़ लिया और जांच शुरू कर दी है।

सुकमा जिले में धान के खेतों में पत्ती मोड़क कीट का दिखा प्रकोप

कृषि वैज्ञानिकों ने नियंत्रण और उपचार के बताया प्रभावी उपाय

रायपुर। राज्य सरकार कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को कृषि उपचार के लिए निरन्तर सलाह प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश के जिलों में खेती-किसानी में होने वाले बीमारियों को जिलावार चिन्हांकित कर कीटनाशक छिड़काव के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में सुकमा जिले के विभिन्न गांवों में धान के खेतों में पत्ती मोड़क कीट का प्रकोप दिखाई दिया है इसे पत्ति लपेटक या चितरी या सोरटी कहा जाता है। इसके उपचार के लिए कीटनाशक छिड़काव के विधि और तरीके बताए गए हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र, सुकमा के कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के मुरतोण्डा, पेरमापारा, नीलावरम, तोगपाल, सोनाकुकानार, नयानार, रामपुरम का मैदानी भ्रमण के दौरान धान के खेत में पत्ती मोड़क कीट का प्रकोप पाया गया, इसे पत्ति लपेटक या चितरी या सोरटी कहा जाता है। इस कीट की इल्ली अवस्था फसल को नुकसान पहुंचाती है इस कीट की इल्ली अपने लार द्वारा पत्ती की नोंक को या पत्तियों के दोनों सिरो को चिपका लेती है इस तरह इल्ली इसके अंदर रहकर पत्तियों के हरे भाग

(क्लोरोफिल) को खुरच खुरच कर खा जाती है जिसके कारण पत्तियों पर सफेद धारियां दिखाई देती है, जिसकी वजह से पत्तियों में भोजन बनाने की प्रकिया नहीं हो पाती है। कीट द्वारा ग्रसित पत्तियाँ बाद में सुखकर मुरझा जाती हैं व फसल की बढ़वार भी रूक जाती हैं। इसके नियंत्रण और उपचार के लिए, कृषि वैज्ञानिकों ने प्रभावी उपाय अपनाने किसानों को सलाह दिया। जिनमें खेतों एवं मेड़ों को खरपतवार मुक्त रखें। संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करें। खेतों मे चिड़ियों के बैठने के लिए टी आकार की पक्षी मीनार लगाए। रात्रि चर कीट को पकड़ने के लिए प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप खेतो में लगाए। अण्डे या इल्ली दिखाई देने पर उसे इकट्ठा करके नष्ट करें। कीट से प्रभावित खेतों में रस्सी चलाएं।

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि बारिश रुकने व मौसम खुला होने पर कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कराये। क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी. 1250 मि.ली. प्रति हेक्टेयर या कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50० एस.पी. 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर या क्लोरेंटानिलिप्रोएल 18.5० एस.सी. 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार्ब 15.80 प्रतिशत ई.सी.200 मि.ली. प्रति हेक्टेयर का उपयोग करके प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक न होने पर 15 दिन बाद दूसरे कीटनाशक का छिड़काव करें और अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके ही रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें।

आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती : अपने ही गांव में नौकरी करने का अवसर

रोजगार की राह देख रहे महिलाओं के लिए खुशखबरी

बलौदाबाजार। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए महिलाओं को आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सोनाखान एकीकृत बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के 59 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

कार्यालयीन समय में शाम साढ़े पांच बजे तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा में अपना आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

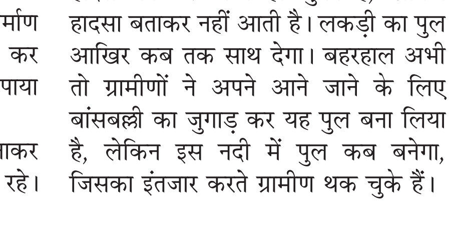

आंगनबाड़ी सहायिका के 59 पदों के लिए ठाकुरदिया, पैरागुड़ा, भरका, टेमरी-2, खैरवारडीह, बफरा, पिपरछेड़ी-2, दौनाझर, डाढ़ाखार, झालपानी, कटवाझर, नवाडीह, घिरघोल, अल्दा, डिपरापारा (रिको), पुरानीबस्ती (अ), त्रिकुटीडीपा (अ), दानीडीपा, रूनझुनी, नवाडीह, लुकाउपाली, तेन्दुचुवा, मेड़ीडीपा, तालाझर, अकलतरा, सैयभाठा, बल्दाकछार-3, दलदली, मुरूमडीह, कौहाबाहर, ठेलकाडबरी, नदीपारा(सो), डिपरापारा (सो), बंसुलीडीह, कलमीदादर, त्रिकुटीपारा (चां), डिपरापारा (थ), तिलसाभाठा, पकलाडीपा, सड़कपारा, बोदापाली, आमापारा, शुकलाभाठा, पुरानीबस्ती, मिरगिदा, बिटकुली, चनाट, सलिहाभाठा, जोगीडीपा, सारसडोल, देवतराई, पचपेड़ी, पोड़ी, जुनाडीह, मंगलडीपा, मुगुलभाठा, बलारनवागांव, कोर्राडीह एवं अचानकपुर आंगनबाड़ी केन्द्र शामिल हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री साय ने दिल के आपरेशन लिए स्वेच्छानुदान से दिए 5 लाख रूपये

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने

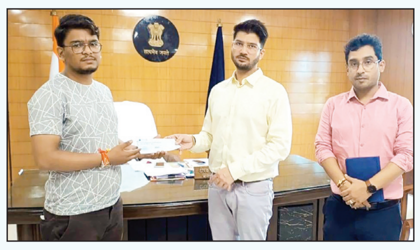

स्वेच्छानुदान मद से बलौदाबाजार भाटापारा निवासी देवा केसरवानी पिता शंकर केसरवानी के लिए 5 लाख रूपये स्वेच्छानुदान से दिया है। उक्त राशि देवा केसरवानी के गंभीर दिल के आपरेशन (हृदय संबधित) उपचार हेतु प्रदान किया गया है। आज कलेक्टर दीपक सोनी ने देवा केसरवानी को स्वेच्छानुदान की 5 लाख रूपये का चेक भेंट किया. स्वेच्छानुदान से राशि मिलने पर देवा केसरवानी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार आभार जताया है।.

मुख्यमंत्री साय से कवर्धा राजपरिवार की रानी श्रीमती कृति देवी ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शुक्रवार को उनके निवास कार्यालय में त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरा-पूर्व लोकसभा क्षेत्र की सांसद एवं कवर्धा राजपरिवार की रानी श्रीमती कृति देवी ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उनके पति कवर्धा राजपरिवार के राजा एवं पूर्व विधायक श्री योगेश्वरराज सिंह भी मौजूद थे।

सरयूपारीण ब्राह्मण सभा का सम्मान समारोह रविवार को

रायपुर। सरयूपारीण ब्राम्हण सभा रविवार की संध्या 6 बजे सरयूपारीण सभा भवन रिंग रोड संजय नगर में अभिनन्दन एवं सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम माननीय न्यायमूर्ति श्री टी पी शर्मा (प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़) मुख्य अतिथि एवं राजेश्री महंत डॉ रामसुन्दर दास (पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष गो सेवा आयोग) विशेष अतिथि के रुप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में समाज के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक शारदा प्रसाद तिवारी, टी डी त्रिपाठी, रमाकांत शुक्ला भी शामिल होंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे समाज के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान किया जाएगा। संस्कृत वेद वेदांत व ज्योतिष के क्षेत्र डॉ दादु भाई त्रिपाठी, आचार्य यदु वँशमणी त्रिपाठी, आचार्य मुक्तिनारायन पांडे, न्यायिक क्षेत्र डॉ सौरव मिश्रा अधिवक्ता, रमाकांत मिश्रा अधिवक्ता एवं सामाजिक क्षेत्र में मनोज शुक्ला, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनिरुद्ध दुबे, केपी शुक्ला, बृजेश द्विवेदी, ओपी मिश्रा, मोहन तिवारी, ज्ञानेंद्र तिवारी, जेपी त्रिपाठी, लवकुश शुक्ला, गौरव शुक्ला, अभिषेक शुक्ला व अनिल तिवारी शामिल है।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने बनी कमेटी, साय बनाए गए अध्यक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। वन मंत्री केदार कश्यप और खेल मंत्री टंक राम वर्मा समेत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी को सदस्य, सचिव बनाए गए हैं। इसका आदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जारी किया है। बता दें कि 2015 से उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी नहीं मिली है। पिछले 9 साल से ये खिलाड़ी नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, खेल मंत्री, और खेल विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। अब इसके लिए कमेटी गठित की गई है। सीएम हाउस में कमेटी की बैठक के बाद खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। पिछली सरकार में कई बार खिलाड़ियों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। बता दें कि 29 अगस्त को खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कई बार खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री साय और खेल मंत्री टंक राम वर्मा को शासकीय नौकरी देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

हाईकोर्ट ने भाटिया वाइंस को लगाई फटकार कहा- क्या लोगों को जहर पिलाओगे

बिलासपुर। भाटिया वाइंस को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तो क्या लोगों को जहर पिलाएंगे। लोगों के जानमाल की चिंता भी है या नहीं। अब मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी। बता दें कि मुंगेली जिले के धूमा स्थित भाटिया वाइंस से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से शिवनाथ नदी में हजारों मछलियों की मौत हो गई थी। मीडिया की खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। जनहित याचिका के रूप सुनवाई की जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान 30 जुलाई 2024 को पर्यावरण संरक्षण मंडल ने हाईकोर्ट को बताया कि जांच के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई गई है। 13 अगस्त को बोर्ड ने बताया कि 22 और 23 जुलाई को फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया था। फैक्ट्री में शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि जहां फैक्ट्री का जहरीला पानी छोड़ा जा रहा था वहां ऑक्सीजन का स्तर शून्य था। इस पर क्षेत्रीय कार्यालय ने 8 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया और खामियों को दूर करने कहा। इधर भाटिया वाइंस ने सुनवाई के दौरान बताया कि पेनाल्टी जमा कर कमियां दूर कर ली गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नियमों के अनुसार फैक्ट्री खोलने पर उचित आदेश जारी करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण मंडल स्वतंत्र है।

हाईकोर्ट के निर्णय से कांग्रेस के घोटाले का हुआ पर्दाफाश : किरण देव

रायपुर। ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर और विवेचना को चुनौती देते हुए अनिल टूटेजा, यश टूटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, नीतेश पुरोहित आदि द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। कुल 13 याचिकाओं में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में ईडी की पुन्ऱ की जा रही कार्रवाई और ईओडब्ल्यू व एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्हें ख़ारिज करने की मांग की गई थी, जिसे एक साथ खारिज करते हुए अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक संगठित अपराध की तरह इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, ऐसा लग रहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की डिवीजन् बेंच ने अपने आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2024 द्वारा आरोपियों द्वारा दायर सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर यह टिप्पणी की गई है कि संबंधित एफआईआर के अवलोकन से, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति से राज्य के खजाने को भारी

वित्तीय नुकसान हुआ है और अपराध की अनुमानित आय लगभग रु. 2,161 करोड़ है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित इस पूरे मामले की विस्तार चर्चा करते हुए कहा कि एफआईआर के अनुसार आबकारी विभाग की मुख्य जिम्मेदारियां शराब की आपूर्ति को विनियमित करना, जहरीली शराब की त्रासदियों को रोकने के लिए उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करना और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करना है। लेकिन अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दिया है। ढेबर और टुटेजा ने शराब नीति को अपनी सनक और पसंद के अनुसार व्यवस्थित रूप से बदल दिया है और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ उठाया है। चूँकि कांग्रेस शासनकाल में सीएसएमसीएल का प्रबंधन बदल गया और यह सिंडिकेट के हाथों में एक उपकरण बन गया, जिसने इसका इस्तेमाल समानांतर व्यवस्था को लागू करने के लिए किया। इस सिंडिकेट में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता, उनके सहयोगी और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी शामिल हैं। फरवरी, 2019 में, अरुणपति त्रिपाठी (आईटीएस अधिकारी) को सीएसएमसीएल का नेतृत्व करने के लिए सिंडिकेट द्वारा चुना गया था और बाद में, मई, 2019 में, अनवर ढेबर के आदेश पर उन्हें संगठन का प्रबंध निदेशक बनाया गया था। साजिश के हिस्से के रूप में, अरुणपति त्रिपाठी को मेसर्स सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब पर एकत्रित रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और सीएसएमसीएल द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था। श्री देव ने कहा कि ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान पता चला कि प्रदेश में एक आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था जो शराब की बिक्री में अवैध कमीशन वसूल रहा था और सरकारी शराब की दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब की अनधिकृत बिक्री में भी शामिल था। अनुमान है कि संदिग्धों द्वारा लगभग 2,161 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की गई है।

देव ने कहा कि उच्च न्यायालय ने माना है कि एफआईआर में नौकरशाहों, राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 70 नामित व्यक्ति हैं और वर्तमान में यह एक संगठित अपराध का मामला है, जिसे जांच एजेंसियों द्वारा तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की जरूरत है। राज्य पुलिस प्रतिवादी राज्य/एसीबी ईओडब्ल्यू या ईडी की कोई भी कार्रवाई पीएमएलए के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं पाया गया है। न्यायालय ने साफ-साफ यह कहा है कि ईडी, ईओडबलू और एसीबी ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार ही इस पर अलग-अलग कार्रवाइयाँ की है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सवाल केवल शराब घोटाले का ही नहीं है। इसी तरह कोयला घोटाले से लेकर हाल के बलौदाबाजार उपद्रव तक, जिसमें आरोपी कांग्रेस विधायक की जमानत याचिका भी खारिज करते हुए देवेंद्र यादव को सात दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

राज्य में पिछड़ा वर्ग समूह के आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक और राजनैतिक भागीदारी का अध्ययन

■ आर.एस. विश्वकर्मा की अध्यक्षता में 12 अगस्त से सर्वे का काम प्रारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक भागीदारी पर अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। आयोग अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2024 में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति-समूह के संदर्भ में यदि कोई शोध अध्ययन करना चाहते हो तो ऐसे शोधार्थी 30 सितम्बर तक आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। इस आशय के अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 27 जून 2020 को प्रकाशित भी की गई है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में कुल 87 जाति समूह को शामिल किया गया है, जिसकी सूची छत्तीसगढ़

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाईट ़ण्बहवइबण्बवउ में उपलब्ध है। शासन द्वारा आयोग के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए श्री आर.एस. विश्वकर्मा को अध्यक्ष, श्री निलाम्बर नायक, श्री हरिशंकर यादव, श्री यशवंत वर्मा, श्री कृष्णा गुप्ता, श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा को सदस्य मनोनीत किया है। आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर आयोग द्वारा राज्य शासन को उक्त अधिसूचना के क्रमांक 02 अंतर्गत पिछड़ा वर्ग समूहों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सहित अन्य विषयों पर अध्ययन कर शासन को सुझाव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

आयोग द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन, शासन के विभिन्न विभागो की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को सौंपा जाएगा। इसी प्रकार राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लामो का अध्ययन। राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आंकलन तथा इसमें वृध्दि की उपाय, राज्य में पिछड़े वर्ग की युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यकमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य उपाय तथा अनुशंसा भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट से राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा।

रिटायर्ड आईपीएस मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

■ एसीबी ने पेश की क्लोजर रिपोर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार में तत्कालीन डीजी आईपीएस (रिटायर्ड) मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में सीजेएम कोर्ट ने एक क्लोज़र रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों में लगाए गए आरोपों में कोई वास्तविक अपराध नहीं पाया गया। यानी जो आरोप लगाए गए वह अपराध हुए ही नहीं हैं।

भूपेश बघेल सरकार ने मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर अवैध इंटरसेप्शन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। इन मामलों में दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

बता दें, आरोपित व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जा सकता है यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, यदि अपराध साबित होता है लेकिन साक्ष्य नहीं होते हैं तो केस समाप्त किया जाता है, और यदि अपराध नहीं हुआ है तो केस खारिज कर दिया जाता है। एसीबी और ईओडब्लू ने जांच के बाद यह सिफारिश की है कि आरोपित मामलों में अपराध नहीं हुआ और इसलिए केस खारिज किया गया है।

क्लोज़र रिपोर्ट में एसीबी ने कोर्ट को बताया कि बगैर अनुमति के इंटरसेप्शन का आरोप पूरी तरह निराधार है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जो भी इंटरसेप्शन हुआ, वह कानूनी और वैध तरीके से किया गया था।

राज्य सरकार की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि एसीबी और ईओडब्लू के तत्कालीन निदेशक जीपी सिंह ने गवाहों पर दबाव डाला और धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने गवाहों से बयान अपने मन मुताबिक कराए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

रिपोर्ट के अनुसार, एसीबी ने जिन धाराओं में अपराध दर्ज किया, उन धाराओं में अपराध दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था। कोर्ट को बताया गया है कि एसआईटी का गठन बिना कोर्ट की अनुमति के किया गया और इसका इस्तेमाल कोर्ट के आदेश की अवहेलना के रूप में किया गया।

क्लोज़र रिपोर्ट के साथ पेश किए गए पत्र में एसीबी ने अदालत से दोनों एफआईआर को खारिज करने की सिफारिश की है। इन एफआईआर के तहत मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें आरोप था कि इन्होंने अवैध तरीके से कॉल इंटरसेप्शन किया और इसके आधार पर कार्रवाई की।

सीएम साय की पहल, 800 सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन शुरू

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में बच्चों के कौशल उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन को शामिल करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ सरकार ने मैजिक बस

इंडिया फाउंडेशन के साथ एक तीन साल की साझेदारी की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुरूप है, और इसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यक स्किल्स और शिक्षा प्रदान करना है।

इस समझौते के तहत, पहले दो शैक्षणिक वर्षों में 800 सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन को लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 1,600 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे 40,000 छात्रों, जो कक्षा 6 से 10 तक के होंगे, को स्किल और जीवन कौशल शिक्षा प्रदान कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत कांकेर और कोंडागांव से होगी और इसे धीरे-धीरे राज्य के सभी 33 जिलों में फैलाया जाएगा।

मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सीईओ, जयंत रस्तोगी, ने कहा कि स्किल एजुकेशन किशोरों के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का भी निर्देश दिया है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास, विशेषकर दुर्गम आदिवासी इलाकों के बच्चों के लिए, विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण क़दम है। स्कूली शिक्षा में स्किल एजुकेशन के नए अवसर देकर, यह कदम राज्य को सशक्त करेगा और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। युवा पीढ़ी नई तकनीकों और ज्ञान से लैस होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस की प्रेसवार्ता निशाने पर गुरु बालदास और गुरु खुशवंत

पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा- ये गुरु अवसरवादी, असली तो सिर्फ बाबा गुरु घासीदास हैं

रायपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए गुरु बालदास पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास सतनामी समाज के असली गुरु हैं। सभी बाबा गुरु घासीदास को मानते हैं। बाबा जी के वंश में पैदा होने से कोई गुरु नहीं हो जाते। समाज के 80 प्रतिशत लोग गुरु प्रथा को बंद करना चाहते हैं। सतनामी समाज एक है। ये गुरु अवसरवादी लोग हैं, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की ओर थे, अब भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा आगे कहा कि जो गुरु भाजपा में चले गए हैं, उनकी स्वीकारता अब नहीं रह गई है।

बता दें, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू और शिव डहरिया ने मिलकर प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री डहरिया ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने

बीजेपी की अंग्रेजों से तुलना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जैसी कार्रवाई की, अंग्रेजों ने भी नहीं किया था।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार सतनामी समाज और कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ने ऐसी कार्रवाई की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से षड्यंत्र खिलाफ लड़ेगी। सरकारी दमन से कांग्रेस डरने वाली नहीं। इस दौरान प्रेसवार्ता में विधायक इंद्र साव और एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी रहे मौजूद।

पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि अमर गुफा में जैतखंभ को काटने का काम किया गया। तीन मजदूरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। सतनामी समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। प्रशासन ने जांच नहीं की। 3 घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा। सरकार का इंटेलीजेंस फेल हो गया था। कलेक्ट्रेट सहित एसपी कार्यालय को जला दिया गया।

उन्होंने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बलौदाबाजार मामले के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रतिनिधियों को जेल में डालने का काम किया गया। इस तरह की कार्रवाई कभी अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। सरकार की साजिश को कांग्रेस बेकनाव करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। सरकार का आतंकी व दोहरा चेहरा है उसे बेनकाब करेंगे।

पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन शुरु

प्रधानमंत्री जनमन योजना : पीएम 15 सितंबर को मेगा ईवेंट में होंगे वर्चुअल रूप से शामिल, विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों से करेंगे संवाद

रायपुर। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेतामआदिम जाति कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम की पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाडिया एवं बिरहोर बाहुल बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 23 अगस्त से 10 सितंबर तक मेगा अभियान चलेगा। राज्य के 18 जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) संचालित है। इन जिलों में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आगामी सितम्बर माह में मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन का आयोजन होगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्य में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड में आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय मेगा ईवेंट में शामिल होंगे तथा देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति वाले किसी एक जिले में राज्य स्तरीय मेगा ईवेंट के लिए चिन्हित किया जाएगा।

मंत्री श्री नेताम ने बताया कि मेगा ईवेंट के अतिरिक्त बाकी सभी पीएम-जनमन के जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन सभी आयोजनों में झारखण्ड राज्य से प्रधानमंत्री का संबोधन और संवाद सुचारु रुप से देखने और सुनने के लिए टू-वे-कनेक्टिविटी की आवश्यक व्यवस्थाएं की

जा रही है। इन आयोजनों में स्थानीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंत्री श्री नेताम ने बताया कि लाभार्थी सतृप्ति शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच एव मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं आदि से लाभान्वित की जानी है। इसका उद्देश्य सभी पीवीटीजी बसाहटों में तात्कालिक गतिविधियों की शत-प्रतिशत संतृप्ति की जानी है।

लाभार्थी संतृप्ति शिविर गहन रूप से सभी पीवीटीजी बसाहटों, जिलों में चलाए जाएंगे। इस लाभार्थी संतृप्ति शिविर का मुख्य फोकस यूआईडीएआई के तहत नामांकन एवं आधार कार्ड जारी करना पीएम जनधन के तहत बैंक खाता खोलना, सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी कर वन अधिकार पत्र जारी करना तथा पीवीटीजी बसाहटों में सिकल सेल बीमारी की जांच आदि कार्य किए जाएंगे। पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों जैसे प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), संपर्क सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, नल से जल, विद्युतिकरण आदि की जानकारी दी जाएगी।प्रदेश में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशऱ बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाडिया एवं बिरहोर जनजाति समूहों तथा बसाहटों के त्वरित विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना क्रियान्वित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इन वर्गों का समग्र विकास करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा इन वर्गों के उत्थान के लिए प्रारंभ किया गया यह महाअभियान अल्प समय में ही लोकप्रिय हो रहा है।

राहुल ने फिर की हिन्दुओं को बांटने की साजिश

संजय सक्सेना

कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे है, वह देश और समाज के लिये काफी घातक है। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये हिन्दू समाज को बांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यह सिलसिला राहुल ने काफी पहले शुरू कर दिया था। इस साल हुये आम चुनाव के बाद तो राहुल ने हिन्दुओं को बांटने की साजिशें और भी तेज कर दी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पारसी दादा फिरोज घांडी के पौत्र राहुल गांधी अपनी जाति धर्म तो छिपाते हैं पर हर हर हिन्दू युवक से उसकी जाति पूछना वह अपना अधिकार समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि राहुल गांधी के दादा फिरोज घांडी को गांधी उपनाम कैसे मिला? कई किताबें कहती हैं कि घांडी फिरोज का कुलनाम था, जो पारसी धर्म में एक जाति विशेष का उपनाम होता है। फिरोज का उपनाम घांडी लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा था, एक तो घांडी उपजाति वाले पारसियों की आबादी बेहद कम थी दूसरे उस समय तो सब गांधी के पीछे भाग रहे थे। अज्ञानतावश लोग फिरोज घांडी को भी फिरोज गांधी कहकर बुलाने लगे, जिसका फिरोज को फायदा भी मिला, इसलिये उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि वह मरते दम तक पारसी ही रहे उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। पारसी समाज के रीतिरिवाज के अनुसार ही उनकी अंतिम क्रिया हुई थी। खैर, यह सब इस लिये याद आ गया क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हुई एक हत्या के सहारे हिन्दुओं को आपस में लड़ाने के लिये बिसात बिछा रहे हैं। बता दें पिछले दिनों राबयरेली में आपसी लड़ाई झगड़े में पासी समाज के युवक अर्जुन की हत्या कर दी गई थी। यह एक आपराधिक घटना थी जिसे राहुल गांधी ने दलित बनाम सवर्ण सियासत में बदल दिया। अपनी इसी सियासी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिये 20 अगस्त मंगलवार को रायबरेली पहुंचे। उन्होंने यहां अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात की। भरोसा दिया कि उत्पीड़न के मामले को सड़क से सदन तक उठाया जाएगा। राहुल गांधी इस हत्याकांड के सहारे अगड़ों और दलितों के बीच खाई पैदा करने का कुचक्र रचने लगे। बता दें राहुल गांधी दलित समाज के युवक अर्जुन पासी के मामले को लेकर विधानसभा की 103 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उनकी पार्टी यह भी रणनीति बना रही है कि दलितों से जुड़े मुद्दे पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी अब अर्जुन पासी की हत्या का मुद्दा उठाया उत्तर प्रदेश में जाटवों के बाद पासी दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है, जो राज्य की कुल अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है। समाज के लोगों का दावा है कि वे करीब 103 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिसमें 70 सीटें ऐसी हैं, जहां पासी समाज ही निर्णायक भूमिका में हैं। राहुल गांधी यह सब तब कर रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही गोली मारकर अर्जुन पासी की हत्या के मामले में परिजनों की शिकायत पर पांच लोगों पर नामजद एफआईआर की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी का काम अदालत को करना है। इस मामले में बाद में ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि पर भी कुछ संगठनों ने हत्याकांड में शामिल होने का आरोप जड़ दिया. हालांकि, इस संबंध में पुलिस ने कहा है कि परिजनों ने जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है उन पर कार्रवाई की गई है। उधर, रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहां पर जो सभी लोग हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवक को जान से मारा गया है। पूरे परिवार को धमकाया गया है. एक शख्स को मारा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां के पुलिस अधीक्षक हत्याकांड के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। छोटे-छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं।

विपक्ष के होश उड़ाने वाली रणनीति पर काम कर रहे मोदी?

अभिनय आकाश

2014 में 282, 2019 में 303 लेकिन 4 जून 2024 में ये जादुई आंकड़े यानी 272 से दूर 240 पर जा सिमटा। अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाने वाली बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में कई बड़े और कड़े फैसले चुटकी बजाकर ले लिए। लेकिन 2024 में वो देखने को मिल रहा है जो इससे पहले के मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में देखने को नहीं मिला। अबकी बार एनडीए की सरकार इन दिनों मोदी सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसे दो कदम पीछे वापस खींचने पड़ रहे हैं। 12 दिन में तीन अहम फैसले ऐसे हैं जिस पर सरकार बैकफुट पर नजर आई है। मोदी सरकार को अपने फैसले रद्द करने पड़े हैं, वापस लेने पड़े हैं या फिर उसे ठंडे बस्ते में डालने पड़े हैं। संसद में बड़ी धूमधाम से वक्फ बोर्ड के नए कानून का ऐलान हुआ। इसको लेकर बिल भी लाया गया। लेकिन फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया। लेकिन जब विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा किया। उस बिल को भी विड्रो कर लिया गया। ताजा मामला सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती से जुड़ा है। लेटरल एंट्री ये शब्द आपने बीते कुछ दिनों में कई बार सुना होगा। लेटरल एंट्री को आखिरकार सरकार ने रद्द कर दिया है। लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन जैसे तमाम नेता इसकी मुखालफत कर रहे थे। लगातार एक्स पर उसको लेकर पोस्ट कर रहे थे। मीडिया में इसे उठाया जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जो विपक्ष के दवाब के तहत होना चाहिए था।

लेटरल एंट्री यानी बिना कोई यूपीएससी का एग्जाम दिए अलग अलग मंत्रालयों में सचिव, उपसचिव और डॉयरेक्टर जैसे पदों पर नियुक्ति को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 45 खाली पद हैं जिनकी भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को अब वापस ले लिया गया है। लेकर अखिलेश तक ने आंदोलन तक की धमकी दे डाली थी। वहीं एनडीए के घटक दल ने भी खुलकर इसकी मुखालफत की थी। लगातार विपक्ष इसे आरक्षण विरोधी, सोशल जस्टिस विरोधी और सामाजिक न्याय का विरोधी बता रहा था। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में उच्च पदों पर विशेषज्ञता वाले लोगों की एक प्रकार से सीधी भर्ती अर्थात लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन वापस लेने से यही स्पष्ट हो रहा है कि मोदी सरकार दबाव में आ गई।

जैसे ही इस बार लैटरल एंट्री का विज्ञापन आया, विपक्ष ने ऐसे रिएक्ट किया मानो वह ऐसी ही किसी मुद्दे की तलाश में था। दरअसल, नियमों के तहत लैटरल एंट्री में आरक्षण का विकल्प नहीं है। सरकार ने बताया कि लैटरल एंट्री के तहत सिंगल पोस्ट काडर में नियुक्ति में कभी आरक्षण का प्रावधान नहीं रहा है। लेकिन विपक्ष ने इस तर्क को अनसुना करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी इस सिस्टम को बैकडोर से आरक्षण समाप्त करने का जरिया बना रही। राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर हमलावर रुख अपना लिया। उन्होंने न सिर्फ इसे आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम बताया बल्कि आरोप लगाया कि इसके जरिए मौजूदा सरकार संस्थानों में बिना मेरिट के अपने लोगों को नियुक्ति करने का रास्ता साफ करना चाहती है। दबाव केवल विपक्षी दलों का ही नहीं था, बल्कि सहयोगी दलों का भी था। चंद्रबाबू नायडू ने तो लेटरल एंट्री के जरिये अनुभवी लोगों की भर्ती की पहल का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान खुलकर विरोध में आ गए। एक अन्य प्रमुख सहयोगी दल जदयू के नेताओं ने भी लेटरल एंट्री का विरोध कर दिया। इससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाने के पहले अपने सहयोगी दलों से विचार-विमर्श ही नहीं किया। यदि वास्तव में ऐसा नहीं किया गया तो यह उसकी रणनीतिक चूक ही है।

थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे प तमाशा न हुआ। सदन में 8 अगस्त को वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ और इस पर जोरदार बहस भी हुई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका सार गालिब के शेर में है। जैसा की तय था कि इंडिया गठबंधन ने बिल का विरोध किया। कांग्रेस, सपा, एनसीपी शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम और डीएमके ने हंगामा किया। सपा सांसद ने तो खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि सरकार ने इसमें कोई बदलाव किया तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन सब के बीच मोदी सरकार ने इस बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। यानी विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा था कि हमसे राय नहीं ली गई। अब इस कमेटी में सब पक्ष अपनी राय रख सकते हैं। कुल मिलाकर कहे तो ये ठंडे बस्ते में चला गया है। इसको लेकर जेपीसी बना दी गई है। एनडीए की एक सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने ये शर्त रख दी थी कि जेपीसी गठित नहीं होने की सूरत में समर्थन नहीं देंगी।

सरकार ने सबसे पहले 10 नवंबर 2023 को इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा था। इसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया था। विपक्षी दलों का यहां तक आरोप था कि सरकार सेंसरशिप लाने का प्रयास कर रही है। मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बिल को पेश किया। इस बिल को लेकर न केवल विपक्ष बल्कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। फिर मसौदा वापस ले लिया गया है। खबर ये है कि आगे इस पर कोई नया मसौदा नहीं आने वाला है।

इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक में यही चल रहा है कि झुकती है सरकार बस झुकाने वाला चाहिए। 12 दिनों में तीन अहम फैसलों में बुकफुट पर आई सरकार को बैसाखियों के सहारे चलता हुआ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सरकार को चुनावों में आशानुरूप सफलता न मिलने से उसका मोराल डाउन हो गया है। लेकिन कुछ सियासी जानकार इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति भी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दों को लटरा रही है जो थोड़ा विवादित है। आपने दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है वाली कहावत तो सुनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो सरकार अब मुद्दों को हल करने की बजाए लटकाने की अहमियत को समझ चुकी है। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सालों तक राजनीति के केंद्र में रहा और इसने बीजेपी की सीटों को 2 से बढ़ाकर 303 तक पहुंचा दिया। लेकिन ये मामला जब तक फंसा रहा बीजेपी को लाभ मिलता रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2014 और 2019 में 71 और 62 सीटें हासिल की लेकिन मंदिर निर्माण के बाद का हाल सभी को ज्ञात है। कहा जा रहा है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और जनता समस्या के समाधान के बाद इसे भूल जाती है। इसलिए, रणनीति के तहत मुद्दों को तब तक लटकाए रखना जब तक की जनता आंदोलित न हो एक चाल हो सकती है। कम से कम वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ऐसा तो कहा जा सकता है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-2)

गतांक से आगे...

अथर्ववेद के जिस सूक्त में परीक्षत शब्द आया है वह कुन्तापसूक्तों में पहला है। कुन्ताप सूक्त अथर्वसंहितान्तर्गत नहीं है। एक दूसरे साहिब कामसूक्त पर चौंका लगाना चाहते हैं, तीसरे बाल्यखिल्य-सूक्त की चटनी करने को उद्यत हैं। कहा जाता है कि महाशय विश्वबन्धु जी और उनके साथी तो वेदों की अपौरुषेयता में ही सन्देह रखते हैं इसीलिये विगत वर्षों में लाहौर में कई दिनों तक गुप्त शास्त्रार्थ होते रहे हैं।

स्वामी प्रेस (मेरठ) द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति, आर्य ग्रन्थावलि (लाहौर) के समस्त ग्रन्थ तथा अन्यान्य समाजी प्रेसों की छपी पुस्तकों को देखने पर कांट-छाँट और डांट फांट के हृदयविदारक दृश्य आंखों के सामने नाचने लग जाते हैं। औरङ्गजेब आदि यवन बादशाहों ने हमारे ग्रन्थ-भण्डार को फूंक डाला जिससे महामहिम ग्रन्थ लुप्त हो गये, लेकिन इस नई औरङ्गजेबी का कोई ठिकाना है कि ग्रन्थों का रूप ही बदला जा रहा है। हिन्दू जाति के दौर्भाग्य से यदि यह बेढ़ंगी रफ्तार इसी प्रकार कुछ दिनों तक और जारी रही तो ग्रन्थों के वास्तविक स्वरूप का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव हो जसा। इस दल की कतर-व्योंत का पता इससे लग सकता है कि हमने इस दल की ओर से प्रकाशित तीन चार प्रकार की गीताओं को देखा है। एक में सिर्फ तेरह अध्याय हैं, शेष अंश को दूध की मक्खी तरह निकाल फेंका है, यह भास्कर प्रेस मेरठ में पं. भूमित्र शर्मा आर्योपदेशक और शिवदत्त शास्त्री ने छपाई है। दूसरी में केवल 70 श्लोक लिखकर उसे ही यथार्थ गीता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, यह लाहौर में मिलती थी। तीसरी में श्लोक तो सब छाप दिये हैं, परन्तु जो जो श्लोक अपने मनघड़न्त आपा-पन्थ के विरुद्ध देखा, उस पर लम्बी चौड़ी टिप्पणी लिख डाली कि यह प्रक्षिप्त है प्रोफेसर राजाराम इसके सम्पादक हैं। **क्रमशः ...**

वी.वी. गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने

अमृत चंद्र

देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के ब्रह्मपुर में हुआ था। वीवी गिरी का पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। गिरी 24 अगस्त, 1969 से 24 अगस्त, 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। उन्हें साल 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दरअसल, देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की 13 मई 1969 को मौत हो गई। इसके बाद वीवी गिरि को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बाद में फैसला लिया गया कि अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाए। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नाम से मशहूर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच तनातनी का माहौल बन गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इंदिरा गांधी के विरोध को दरकिनार करते हुए नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का निर्णय लिया।

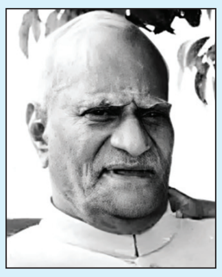

वीवी गिरी 20 साल की उम्र में ही पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास से स्थापित स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए और 1927 से 1930 तक केंद्रीय विधान सभा (अंग्रेजों के शासन के वक्त) के सदस्य रहे। गिरी को पहली बार 1992 में शराब की बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था। 1923 में, गिरी ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के संस्थापकों में से एक बने।

साल 1913 में वकालत की पढ़ाई के लिए वो आयरलैंड चले गए थे, जहां उन्होंने 1913 से लेकर 1916 तक डबलिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही डी वलेरा से हुई। गिरी वलेरा से काफी प्रभावित थे, जिसके चलते वो आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फीन आंदोलन से जुड़े और अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्हें भाग लेने की वजह से आयरलैंड से बाहर निकाल दिया गया। आंदोलन में उनकी मुलाकात कई महान स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। वीवी गिरी देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। साल 1969 में वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बने और उनके निर्वाचन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में वीवी गिरी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। देश के इतिहास में ये भी पहली हुआ था कि किसी मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान देश के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गवाही देने के लिए पहुंचे हों। इसके बाद भी फिर कभी ऐसा नजारा सुप्रीम कोर्ट में देखने को नहीं मिला। ये साल था 1970, जब कानूनी तौर पर छूट हासिल होने के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया था। देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि शुरू से ही मजदूरों के बड़े नेता रहे। साल 1928 में उनके नेतृत्व में रेलवे कामगारों की अहिंसक हड़ताल हुई। ब्रिटिश राज और रेलवे प्रबंधन को कामगारों की मांग माननी पड़ी। ट्रेड यूनियनों को आजादी के आंदोलन का भागीदार बनाने का बड़ा श्रेय वीवी गिरि को दिया जाता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा मोदी लेंगे शांति का नोबल पुरस्कार

अभिनय आकाश

8 जुलाई 2024 को रूस की राजधानी मॉस्को में दोपहर के वक्त आसमान में पंछी जैसी सफेद चीज नजर आई। जैसे-जैसे वो चीज करीब पहुंची उसका आकार बढ़ता गया। कुछ मिनटों के बाद एक विशालकाय विमान वेणुकोवो-ड्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर खड़ी हो गई। इस विमान पर सुनहरे अक्षरों में भारत लिखा था। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे और व्लादिमिर पुतिन को गले लगाती तस्वीर तो आपको याद ही होगी। जिस तस्वीर को देखकर रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलदोमिर जेलेंस्की भड़क गए थे। लेकिन अब पुतिन के बाद पीएम मोदी की जेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आने वाली है। जी हां, पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। 23 अगस्त को पोलैंड से ही ट्रेन के जरिए पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। खासकर रूस- यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इस यात्रा की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। एक महीने के अंदर हो रही प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भारत रूस और यूक्रेन, दोनों के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है और युद्ध का असर अपने किसी रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहता। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति की नीति पर चलता है। पीएम मोदी विभिन्न मंचों से साफ कर चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। पोलैंड से भी पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग को लेकर अपनी पटकथा कि शुरुआत कर दी है। ऐसे में चर्चा तेज हो चली है कि क्या पीएम मोदी दोनों देशों के बीच चल रही जंग को रुकवा पाएंगे? इसके साथ ही चर्चा चल रही है कि पीएम मोदी युद्ध रुकवा कर शांति का नोबेल प्राप्त कर सकते हैं।

पोलैंड में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत, बुद्ध की विरासत वाली धरती है, जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। इसलिए, भारत इस रीजन में भी स्थाई शांति का एक बड़ा पैरोकार है।

भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। भारत का विसडम ग्लोबल है, जिन ग्लोबल है, हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कम्पैशन ग्लोबल है, हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत की नीति और निर्णयों में नजर आता है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, आज का भारत सबके विकास की बात करता है, आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया, भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय रूस यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात को भारी निराशा और शांति प्रयासों के लिए एक झटका करार दिया था। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को दुनिया के सबसे खूनी व्यक्ति को गले लगाते देखना एक बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है।

नई दिल्ली का कीव से पुराना नाता है। भारत यूक्रेन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। जनवरी 1992 में दोनों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। सोवियत काल से पहले और बाद में दोनों देशों ने साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। भारत और यूक्रेन के बीच सहयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कृषि व्यापार ने भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों का आधार बनाया। कीव ने 2021 में .2 बिलियन से अधिक मूल्य का निर्यात किया। हालाँकि, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है। 2022 में भारत-यूक्रेन व्यापार की मात्रा एक साल पहले के 3.38 बिलियन डॉलर से घटकर 2.58 बिलियन डॉलर हो गई। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, जहां यूक्रेन को भारत का निर्यात 22.8 प्रतिशत घटकर 85.49 मिलियन डॉलर हो गया, वहीं भारत को यूक्रेन का निर्यात 17.3 प्रतिशत गिरकर 1.69 बिलियन डॉलर हो गया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को एक नहीं दो-दो बार रोकने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन लाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था और कामयाबी हासिल की। जगशंकर ने बताया कि अगर आप मुझसे यूक्रेन और रूस युद्ध रोकने की बात करेंगे तो मैं इसका गवाह हूं। हमने एक नहीं दो बार ऐसा काम करके दिखाया है। पहली बार 5 मार्च को पीएम मोदी ने व्लादिमिर पुतिन को फोन किया और हमारे छात्रों के लिए रास्ता बनाने के लिए गोलीबारी रोकने को कहा। पीएम मोदी के अनुरोध पर रूसी सेना ने गोलीबारी रोकी ओर हमारे लोग वतन लौटे। अगली सफल कोशिश 8 मार्च थी। तब पीएम मोदी ने पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की और अपने छात्रों के लिए रास्ता बनाया। गोलीबारी रोकी गई और हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया गया।

दिलचस्प है कि जब पीएम मोदी कीव पहुंच रहे हैं तब यूक्रेन की सेना ने कुछ रूसी क्षेत्रों में दबाव बढ़ा रखा है। लेकिन भारत युद्ध के उतार-चढ़ावों से खुद को अलग रखे हुए है। उसका शुरू से कहना है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही सारे विवाद हल किए जाने चाहिए। पीएम मोदी जब 2022 में समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, तब भी उनसे कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है और जब हालिया रूसी यात्रा के दौरान उनसे मिले तब भी कहा कि युद्ध के मैदान में कोई हल नहीं निकलने वाला।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से आह्वान किया कि वह रूस के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों का उपयोग करके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में अपने अवैध युद्ध को समाप्त करने के लिए कहे। चाहे रूस और यूक्रेन हों या अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश, भारत किसी के भी दबाव में आए बगैर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र और संतुलित नीति पर कायम है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी आज भी यह उम्मीद बनाए हुए है कि दोनों देशों से करीबी की बदौलत भारत शांति प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभा सकता है।

आज का इतिहास

1892 इंग्लैंड के लिवरपूल में गुडिसन पार्क, जो दुनिया के सबसे पहले निर्मित फुटबॉल मैदानों में से एक है।

1908 मोरक्को के सुल्तान अब्दलिज़ज़ को बहुत ही संघर्ष के बाद हतोत्साहित किया गया है, और उनके भाई अब्द अल-हफीद को मोरक्को का उत्तराधिकारी बनाया गया

1926 पावलोस कुंटोरायोटिस को ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गयी।

1942 द्वितीय विश्व युद्ध के विमानवाहक पोत शरतोगा से द्वितीय विश्व युद्ध के बमवर्षकों ने मित्र देशों की जीत के लिए सांता इजाबेल, सोलोमन द्वीप के पास जापानी विमानवाहक रयुजो को डूबो दिया।

1963 बौद्ध संकट-अमेरिकी विदेश विभाग ने राजदूत दक्षिण कैबोट लॉज, जूनियर को आदेश दिया कि अगर वह स्वेच्छा से अपनी सत्ता की स्थिति से नागो दीन्ह नु को हटाने के लिए, दक्षिण वियतनामी सेना के अधिकारियों को नगो दीन्ह दीम को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करे।

1968 पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट करने के बाद, फ्रांस दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया।

1973 घोड़े के पूर्वी इंसेफेलाइटिस और घोड़े के मस्तिष्क को संक्रमित करने वाली बीमारी ने मास और आसपास के राज्यों में 50 घोड़ों को मार दिया है। रोग का कारण कीटनाशक, मैलाथियोन है, जो मच्छरों को मारने के लिए हजारों एकड़ में फैला हुआ है।

1992 चीन और दक्षिण कोरिया ने राजनयिक संबंध स्थापित किए।

1992 तूफान एंड्रयू ने दक्षिण फ्लोरिडा में तीसरा सबसे शक्तिशाली श्रेणी 5 सिस्टम बनाया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को 20 वें दशक के दौरान हिट करने के लिए बनाया गया था।

1998 यूनाइटेड किंगडम में पहली आरएफआईडी मानव आरोपण का परीक्षण किया गया।

2004 आत्मघाती हमलावरों द्वारा मास्को के डोमोडेडोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर उड़ान भरने वाले हमलावरों पर हमला करने के बाद लगभग 90 लोगों की मौत हो गई।

2005 स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भारी बाढ़ ने हजारों लोगों को निकाला।

2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (ड्ड) ने पहली बार %ग्रह% शब्द का निर्धारण किया और घोषणा की कि प्लूटो किसी भी अधिक हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं था, इसे %बौने ग्रह% के रूप में घोषित किया गया। प्राग में एक बैठक में 2,500 वैज्ञानिकों ने वोट से तय किया कि प्लूटो को एक वैज्ञानिक समुदाय में ग्रह नहीं माना जाएगा।

मोदी की एक लाख युवाओं को राजनीति में लाने की क्या है मंशा

संजय सक्सेना

देश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब छात्र संगठनों, स्कूल कालेजों और विश्वविद्यालयों से युवा छात्र नेताओं की पौध नहीं तैयार होती है। आम युवा पीढ़ी की भी राजनीति में रूचि घटती जा रही है। यहां तक की देश के आगे ले जाने के लिये होने वाली समसामयिक राजनैतिक चर्चाओं से भी यह दूर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस बात पर चिंता जता कर समाज को आईना दिखाने का काम किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख गैर-राजनीतिक युवाओं को जन प्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने का आह्वान किया। उनको लगता है कि ऐसा करने से जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने में मदद मिलेगी। मोदी का यह कहना बिल्कुल सही है कि यह युवा अपनी पसंद की किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही पार्टी हो। पीएम मोदी को यह बात इस लिये कहना पड़ी क्योंकि आज का युवा राजनीति से विमुख हो रहा है। राजनीति के क्षेत्र में नये नवेले जन प्रतिनिधि आयेगें तो इससे निश्चित ही राजनीति का स्तर बढ़ेगा। वह लीक से हट कर राजनीति करेंगे। पीएम ने जो कहा है संभवता देश की भी यही इच्छा है,क्योंकि वह भी परिवारवाद और वंशवाद की रानजीति से ऊब चुका है। यह वह युवा होंगे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगी। उनके (युवाओं के) माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, भतीजे कभी भी किसी भी पीढ़ी में राजनीति में नहीं रहे होंगे तो ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं की सोच भी अलग होगी। यह युवा चाहे पंचायत के लिए या फिर नगरपालिका, जिला परिषद या विधानसभा या लोकसभा के लिये चुनाव लड़े,इससे देश को ही फायदा होगा। सबसे बड़ी बात इससे जातिवाद और वंशवाद की राजनीति से छुटकारा मिलेगा।

मौजूदा दौर में बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं का जैसा व्यवहार दिख रहा है, जिस तरह की भाषा का वह इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि यह नेता राष्ट्र के लिए सुचिंतित और परिपक्व भूमिका निभाने को तैयार हैं। चुनावी अभियान में तो भाषाई मर्यादाएं तार-तार होती होती ही रही हैं।लोकतंत्र के मंदिर में भी यही नजारा देखने को मिलता है। झूठ बोलना और जनता को बरगलाना- भड़काना तो राजनीति की एक जरूरत बन गया है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाला राजनीतिक तंत्र जिस तरह चिंतन और सोच के स्तर पर निचले पायदान पर पहुंच गये है, उसकी वजह से यह मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि राजनीति में अब सुचिता बेईमानी हो गई है। हमारे नेता यह मानने को तैयार ही नहीं है कि सियासी संग्राम में भाषाई परिपक्वता की कमी को अनदेखा करना चाहिए, लेकिन क्या व्यापक राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी चलताऊ और स्तरहीन रवैया अपनाया जाना चाहिए? तमाम दलों के नेताओं का किसी घटना की निंदा या समर्थन अपनी राजनीति के हिसाब से करना या नहीं करना देश और समाज दोनों के लिये खतरनाक है। समाज के एक वर्ग के साथ अपना जुड़ाव दिखाना और दूसरे वर्ग को उपेक्षित रखना समृद्ध लोकतंत्र की निशानी नहीं है। इसका ताजा नजारा तब देखने को मिला जब बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप् से चुनी गई शेख हसीना सरकार का सैन्य तख्तापलट हो गया। बांग्लादेश के घटनाक्रम के बाद विपक्षी खेमे में मोदी सरकार के खिलाफ बदजुबानी की जैसे प्रतियोगिता चल निकली। इसमें सबसे खतरनाक बयान उन नेताओं का था जो कह रहे थे कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। इन नेताओं का इशारा मोदी सरकार के साथ भी ऐसा ही घटनाक्रम होने का संकेत दे रहा था। सबसे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान आया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 'जो बांग्लादेश में हो रहा है, वह भारत में भी हो सकता है।'

सलमान खुर्शीद न सिर्फ खानदानी नेता हैं, बल्कि विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि उन्हें कूटनीति की समझ नहीं है। सलमान खुर्शीद के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता।इसके बाद तो ऐसे बयानों की बाढ़ ही आ गई। सलमान एक तरह से देश की मौजूदा सरकार को बदलने के लिए बांग्लादेश जैसी अराजक राह सुझा रहे थे। वह भारत के मौजूदा सरकार विरोधी मानस को संदेश दे रहे थे कि इसे भी इसी तरह हटाया जा सकता है। याद कीजिए मणिशंकर अय्यर को। वह पाकिस्तान जाकर वहां के लोगों से मोदी को सत्ता से हटाने में सहयोग की मांग कर चुके हैं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया, वह भी राष्ट्र की सामूहिक भावना पर चोट करता है। उन्होंने कहा कि अपने तानाशाह को भी याद रखना चाहिए कि जनता ऐसे फैसला लेती है।आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो यहां तक कहा कि जो तानाशाही करेगा, उसे देश छोड़कर जाना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया कि बांग्लादेश की तरह भारत की जनता भी पीएम आवास और गृहमंत्री के आवास में घुसेगी। उद्धव ठाकरे के प्रमुख सिपहसालार संजय राउत ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ, उससे देश के सत्ताधारी सबक लें।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जैसा हाल हसीना का हुआ, हर तानाशाह का यही हाल होगा। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक तो मीम बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को व्यंग्य में समझाने लगीं कि दोस्त यानी हसीना गईं, अब आप बचकर रहो। वह भूल गईं कि शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी की नहीं, भारत की दोस्त रही हैं। उन्हें लंबे वक्त तक शरण उनकी पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने भी दी थी। यह भी न भूलें कि हाल तक शेख हसीना सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी गर्मजोशी से मिलती रहीं थीं। यह वह नेता हैं जो राजनीतिक रूप से मोदी और उनकी सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और जनता भी ऐसे नेताओं को अपना जनप्रतिनिधि चुनने से परहेज करती है।इसीलिये ऐसे तमाम नेता मीडिया या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की साजिश रचते रहते हैं। यह नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिये संवैधानिक सस्थाओं को भी निशाने पर लेने से परहेज नहीं करते है। सबसे खतरनाक खेल यह चल रहा है कि यह लोग पहले तो सार्वजिनक रूप से विवादित बयान देते हैं और जब मानहानि के किसी केस में फंसते हैं तो चुपचाप माफी मांगकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अपने देश के उद्योगपतियों को नीचा दिखाना, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा धूमिल करना,देश में अव्यवस्था फैलाने वाली विदेशी संस्थाओं के बयान और रिपोर्ट पर देश को बदनाम करना इनका एजेंडा बन गया है। यहां तक की न्यायपालिका भी इनसे नहीं बची हैं।

विपक्षी दलों का एक बड़ा धड़ा मोदी और अमित शाह को तानाशाह बताने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। साथ ही उनके खिलाफ बदजुबानी करने का भी अवसर हाथ से जाने नहीं देता। सवाल उठता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये किसी नेता को तानाशाह बताना सही है। फिर मंचों से खुलेआम उसकी कटु आलोचना हो, कई बार वह गाली में तब्दील हो जाये ऐसा दुनिया में अब तक तो नहीं देखा गया है कि तानाशाह की लानत-मलामत की जाए, उसे अशोभनीय भाषा से निशाना बनाया जाए,फिर भी ऐसे आरोपी खुले में घूमते रहे, लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है। यह शर्मनाक और निंदनीय दोनों ही है। विपक्षी दलों के नेता बाबा साहब के संविधान को अपना राजनैतिक मोहरा तो बनाते हैं लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि राष्ट्र के प्रतिनिधित्व की बात करें या प्रतीक की, केंद्रीय सत्ता को ही संवैधानिक रूप से देश का प्रतिनिधि या प्रतीक माना जाता है। लिहाजा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर केंद्र सरकार की राय को ही राष्ट्र की राय माना जाता है। कुछ समय पहले तक अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक मामलों पर समूचा देश एक जैसी राय रखता था, लेकिन जब से राहुल गांधी,अखिलेश यादव,तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने परिवारवाद की राजनीति की बागडोर संभाली है तब से सियासत का स्तर काफी गिरा है। आम आदमी पार्टी भी इसके लिये ओवैसी जैसे नेता भी कम कसूरवार नहीं है। ऐसा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले भी विपक्ष के सुर सरकारी सुर से मिलते ही रहते थे, लेकिन कम से कम तमाम दलों के नेता इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर करने से बचता था। कुछ मतभेद हुए भी तो उन्हें सीमाओं के अंदर ही दूर कर लिया गया, लेकिन राष्ट्र एक सुर में बोलता रहा, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सवाल सही-गलत का नहीं विरोध के लिये विरोध करने का होता है।

खैर, सत्ता पक्ष को भी इसके लिये क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है इसके लिए किंचित दोषी सत्ता पक्ष भी है। क्योंकि अब वह विपक्ष की राय लेना ही उचित नहीं समझती है। होना तो यह चाहिए कि देश और लोकहित में राष्ट्रीय स्तर पर एक राय रखी जाए। अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाए, लेकिन अब तो जिम्मेदार लोग गालियां तक देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश का मामला कोई पहला मौका नहीं है, जब सियासत की ओर से स्तरहीन बयानबाजी की गई हो। इजरायल और हमास के आतंकवादियों के बीच जंग में भी यही देखा गया था। जब कट्टपंथियों ने ही नहीं कांग्रेस जैसी राजनैतिक पार्टियों ने भी इसे फिलिस्तीन से जोड़कर मुसलमानों पर अत्याचार बताना शुरू कर दिया था। याद करें कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहरा दिए जाने पर कैसे बचकाने बयान दिए गए। किस राज्य के खिलाड़ियों ने मैडल जीता, किसने नहीं, इसका विवाद खड़ा किया जाता है।हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सेबी पर उंगली उठाई जाती है। अपने देश के उद्योगपतियों पर हमला बोला जाता है।

क्या यह जन्मजात योद्धा ममता के अंत की शुरूआत है

जूलियो रिबैरो

पश्चिम बंगाल में 2 दशकों तक राजनीतिक क्षेत्र में छाई रहने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी की दबंग बॉस आज पूरी तरह बैकफुट पर हैं। क्या यह इस जन्मजात योद्धा के अंत की शुरूआत है? अगर ऐसा है, तो भाजपा वहां सफल होगी, जहां बंगाल की अन्य पार्टियां विफल रहीं। कोलकाता के आर.जी. कर मैडीकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ी एक युवा महिला डाक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले से निपटने में भाजपा ने ममता की कई गलतियों का फायदा उठाया है, जिससे ममता की अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके खिलाफ हो गए हैं। युवा महिला डॉक्टर के साथ उसके कार्यस्थल पर बेशर्मी से क्रूरता की गई। ऐसा लगता है कि युवा पुरुष अपने चुने हुए पीड़ितों का बलात्कार करने और उन्हें मारने के मौके की तलाश में रहते हैं! कड़े कानून बनाने की जोरदार मांग हो रही है, हालांकि कड़े कानून पहले से ही मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय राज्य वास्तव में हमारी इन लड़कियों के बारे में चिंतित हैं या इसका नेतृत्व ऐसे पुरुषों द्वारा किया जा रहा है जो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की तरह यह मानते हैं कि 'लड़के तो लड़के ही होते हैं?' भारतीय संघ के हर राज्य या दुनिया के दूसरे देशों में लड़के ही लड़के क्यों नहीं हैं? इस सवाल का जवाब सत्ता में बैठे लोगों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। यौन विकृतियों के खतरे से निपटने के लिए बहुत कुछ राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। समाधान में नए कानून बनाना शामिल नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यौन दुराचार पर मौजूदा कानूनों को समान रूप से और दृढ़ता से लागू किया जाए। कोलकाता के मैडीकल कॉलेज मामले में, सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में 'सिविक वालंटियर' (नागरिक स्वयंसेवकों) नियुक्त करने की कपटी प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इन कार्यकर्त्ताओं को सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों में से उनके पिछले इतिहास, उनकी आदतों और उनकी प्रवृत्तियों की उचित जांच किए बिना चुना जाता है। हर राजनीतिक दल के तीखे तेवर दिखाने वाले गुंडे तत्वों को घुसने की अनुमति दी जाती है। उन्हें अस्पतालों के परिसर में घूमने और मरीजों को बिस्तर और चिकित्सा सुविधा दिलाने में मदद करने के लिए दिया गया 'अधिकार पत्र' इस दुखद घटना का कारण बना है। कॉलेजों से नियमित रूप से भर्ती किए गए सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को, जो छात्रों को सच्चे सामाजिक कार्य के लिए प्रशिक्षित करते हैं, इन 'नागरिक स्वयंसेवकों' की जगह लेनी चाहिए, जिनका मुख्य काम संकट में फंसे मरीजों से पैसे ऐंठना है। यह खतरा बंगाल या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। गुजरात में मुझे पता चला कि विचारधारा से जुड़े लोगों से भर्ती किए गए शिक्षकों के अलावा, होमगार्ड के रैंक भी उसी पक्षपातपूर्ण स्रोत से चुने गए थे। होमगार्ड को अक्सर कानून और व्यवस्था या यातायात विनियमन कर्त्तव्यों में पुलिस की सहायता के लिए भेजा जाता है। अगर अप्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं की इस तरह की भर्ती बंद नहीं की गई तो कोलकाता में हुई घटना जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। यौन दुराचार के मामलों को कम करने का एक और बहुत जरूरी उपाय यह है कि संभावित अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि वे सत्ता में बैठी पार्टियों से किसी तरह की दया की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्हें पुलिस पकड़ लेगी और अदालतें सजा सुनाएंगी। वर्तमान में राजनीतिक दलों द्वारा एक बहुत ही गलत संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि अगर आप सत्ता में बैठी पार्टी का समर्थन या मदद करते हैं तो जेल में आपकी अवधि आसानी से मिलने वाले पैरोल और यहां तक कि जेल की सजा की समय से पहले समाप्ति के कारण कम हो जाएगी। हरियाणा में बड़ी संख्या में अनुयायियों वाले एक धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम को दो बलात्कार और एक हत्या का दोषी ठहराया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समय उन्हें लंबे समय के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। इससे पार्टी को कुछ और वोट पाने में मदद मिली होगी, लेकिन यौन अपराधियों को अपनी हवस मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह, गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान महिलाओं से बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दर्जन भर लोगों को समय से पहले रिहा कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि पक्षपातपूर्ण सरकार ऐसे अपराधियों की सहायता और उन्हें बढ़ावा देने से नहीं रुकेगी, भले ही महिलाओं का शोषण किया गया हो, जब तक कि वे पार्टी के समर्थक हैं। सौभाग्य से कोलकाता उच्च न्यायालय ने उस समय हस्तक्षेप किया जब वहां की सत्तारूढ़ पार्टी आर. जी. कर अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति बहुत दयालु थी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सिविक वालंटियर्स की गैर-कानूनी गतिविधियों के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिन्हें पहले से ही 12,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सजा चौकी पर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक बेहतर और बड़ा अस्पताल मिला। निर्णय की उस त्रुटि को व्यापक रूप से टी.एम.सी. द्वारा अस्पताल के प्रबंधन में मूलत॒ बुराई को समर्थन देने के संकेत के रूप में व्याख्यायित किया गया। भाजपा नेतृत्व को अपने सांसद बृजभूषण सिंह को हटाने में काफी समय लगा, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी थे। वह एक सीरियल अपराधी थे, लेकिन उन्होंने अपने गृह नगर और उसके आसपास कई शैक्षणिक संस्थान चलाए। उन्होंने 3 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में वोट हासिल किए। और यह बात भाजपा के लिए अधिक मायने रखती थी। महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देने वाले सभी नारों और पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा दिन-रात दोहराए जाने वाले नारों से बेहतर है। अगर बृजभूषण के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की गई होती तो विनेश फोगाट को अपने पसंदीदा वजन वर्ग 55 किलोग्राम में ओलिम्पिक कुश्ती स्लॉट के लिए ट्रायल से नहीं चूकना पड़ता। और हमें ओलिम्पिक खेलों में नियमों को बदलने के लिए अंतिम प्राधिकरण से गुहार नहीं लगानी पड़ती!

हरियाणा के चुनावी दंगल में कौन मारेगा बाजी?

राज कुमार सिंह

राजधानी होने के साथ ही देश का दिल भी मानी जाने वाली दिल्ली के तीन ओर बसा हरियाणा आकार और आबादी में छोटा है, लेकिन खेल से राजनीति तक उसकी धमक बड़ी रहती है। केंद्रीय सत्ता के लिए अप्रैल-जून के बीच हुए चुनावों के बाद अब हरियाणा की सत्ता के दंगल का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि मतदाताओं ने हरियाणा की सत्ता की चाबी किसके हाथों दी। वैसे, हाथ कांग्रेस का चुनाव चिह्न है, जो 10 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है और चाबी उस जेजेपी का चुनावी चिह्न है, जो अपने गठन के साल भर के अंदर ही हरियाणा में 'किंग मेकर' बनकर तो उभरी, पर अब बिखराव के कगार पर है।

हरियाणा की राजनीति दशकों तक तीन चर्चित लालों- बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के इर्दगिर्द घूमती रही। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के चलते भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर मुख्यमंत्री के रूप में जिन मनोहर लाल को चुना, चौथे लाल के रूप में वह राज्य की राजनीति की चाल बदलने वाले साबित हुए। आज तीनों चर्चित लाल परिवार के सदस्य भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं।

2014 में देवीलाल परिवार की पार्टी आईएनएलडी ने 15 सीटों वाली कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया, लेकिन 2019 आते-आते सब कुछ बदल गया। देवीलाल परिवार में विभाजन से जेजेपी जन्मी और आईएनएलडी में ऐसी भगदड़ मची कि कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया। अब जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जेजेपी में भी वैसी ही भगदड़ है। 10 में सात विधायक उसे अलविदा कह चुके हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में जेजेपी उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए, जबकि कांग्रेस ने 10 में से पांच लोकसभा सीटें जीत लीं। विधानसभा क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस ने कुल 90 में से 46 में बढ़त हासिल की, जबकि भाजपा ने 44 में।

फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चुनाव और उसके मुद्दे अलग होते हैं। 2019 के चुनाव पर ही नजर डाल लें। भाजपा ने लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतीं, लेकिन चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में 46 सीटों का बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इसलिए हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 विधानसभा क्षेत्रों में मिली बढ़त को एक हद से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव से दो महीने पहले अचानक ही मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने और जेजेपी से गठबंधन भी टूट गया। ऐसे घटनाक्रम का अप्रत्याशित चुनावी प्रभाव और परिणाम होता है।

ऐन चुनाव से पहले होने वाले पाला-बदल का लाभ भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी हुआ है, लेकिन दस साल पहले जिस अंतर्कलह के चलते कांग्रेस की दुर्गति हुई थी, उससे वह आज भी मुक्त नहीं। दस साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और उन्हीं की पसंद से उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बना कर आलाकमान ने उन्हें 'फ्री हैंड' का ही संदेश दिया है। ऐसे में हुड्डा विरोधियों के समक्ष कमल थामने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन अभी भी कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के रूप में दो दिग्गज ऐसे मौजूद हैं, जिनकी आलाकमान तक सीधी पहुंच है। दोनों ही राष्ट्रीय महासचिव हैं।

सिरसा से सांसद चुने जाने के बावजूद सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे कर साफ कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस द्वारा किसी को 'सीएम फेस' पेश करने के आसार कम ही हैं, लेकिन रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह 'हरियाणा मांगे हिसाब' यात्रा निकाल रहे हैं, उसे भूपेंद्र हुड्डा द्वारा अपने बेटे को स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है। जवाब में सैलजा भी अलग यात्रा निकाल रही हैं। यह खेमेबाजी टिकट वितरण में भी दिखेगी।

भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर के आसार का अर्थ यह नहीं कि अन्य दल चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने वाली आप विधानसभा चुनाव अलग लड़ रही है, तो आईएनएलडी ने बसपा के साथ गठबंधन किया है। जेजेपी भी चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी ही। पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुकोणीय मुकाबला भाजपा के लिए अनुकूल होगा, क्योंकि सत्ता विरोधी वोट बंट जाएंगे।

इस सियासी दंगल में सबसे अहम होंगे मुद्दे। हरियाणा में बेरोजगारी की उच्च दर अरसे से चर्चा का विषय है। लेकिन भाजपा के लिए असल चुनौती तीन बड़े 'स्पीडब्रेकर' पार करने की होगी- किसान आंदोलन, महिला पहलवानों के दिल्ली में अनशन से बना माहौल व 'अग्निवीर' के नाम से चर्चित 'अग्निपथ' योजना। विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर साल से भी लंबे चले किसान आंदोलन का ठिकाना हरियाणा ही था। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी ही लाते हैं। सेना में भागीदारी वाले राज्यों में भी हरियाणा अग्रणी है। कांग्रेस स्वाभाविक ही इन सबका चुनावी लाभ उठाना चाहेगी।

राज्य और केंद्र में सत्तारूढ भाजपा को भी इन चुनौतियों का अहसास है। इसीलिए सुधारात्मक कदम उठा कर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश हो रही है, पर इतनी देर से की जानेवाली ये 'कुछ कोशिशें' क्या जनता का मन बदल पाएंगी—हरियाणा का जनादेश बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा।

सत्ता की आत्मसंतुष्टि और शेख हसीना का पराभव

मिहिर एस शर्मा

अब जबकि सब कुछ बीत चुका है तब लगता है कि बांग्लादेश में सत्ता से बेदखल की गईं प्रधानमंत्री शेख हसीना की पकड़ के बारे में लोगों में काफी बेफिक्री या आत्मसंतुष्टि थी। आधिकारिक विपक्षी दल बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की स्थिति भी बेहद खराब होने के कारण आवामी लीग अजेय ही नजर आ रही थी। बीएनपी की नेता खालिदा जिया को 2018 में 17 वर्षों के लिए जेल की सजा सुनाई गई और वह कुछ समय से बीमार चल रही हैं।

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के कई समर्पित कार्यकर्ता उसके साथ बने हुए हैं मगर उसका पिछला रिकॉर्ड और विचारधारा कारगर विपक्ष के तौर बीएनपी की विश्वसनीय विकल्प बनने की राह में आड़े आ रही थीं। संगठित राजनीतिक चुनौती के अभाव में यही लगता थी कि हसीना जब तक चाहेंगी, बांग्लादेश में सत्ता में बनी रहेंगी। हमें पता है कि यह धारणा कितनी गलत थी। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों के नेतृत्व में कई हफ्ते तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद दुनिया में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली महिला शेख हसीना को पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। मगर इसकी वजह हसीना की सरकार और पार्टी के कुछ गलत फैसले भी थे, विशेषकर प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए सड़कों पर हिंसा के इस्तेमाल का उनका प्रयास। हसीना की सरकार को बचाने के लिए की गई हिंसा में कई लोग मौत के शिकार हुए।

सरकारें भले ही तानाशाही क्यों न हों अगर वे प्रदर्शकारियों से निपटने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेती हैं तो उनके बने रहने की संभावना बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर वे ऐसा कदम उठाती हैं तब उन्हें यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास बड़ी संख्या में और लंबे समय तक रहने वाला बल है और सेना का पूरा समर्थन भी हासिल है। कीव में एक दशक पहले मैडन स्क्वैर प्रदर्शन के दौरान रूस के समर्थन वाली विक्टर यानुकोविच सरकार तब चरमराई, जब दंगे पर नियंत्रण करने वाली विशेष पुलिस के साथ झड़प में 100 से अधिक लोग मारे गए। यानुकोविच को सेना से अर्द्धसैनिक बलों के

प्रति समर्थन नहीं मिला और उन्हें भागना पड़ा। उसमें और 4 जून, 1989 में अंतर साफ दिख जाता है, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने थ्येन आन मन चौक पर छात्रों को कुचलने का आदेश खुशी-खुशी मान लिया था और कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता मजबूत हो गई थी।

हसीना को तब सत्ता से बेदखल होना पड़ा जब उन्होंने सेना पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। संभव है कि उन्होंने पिछले एक दशक में सेना को खरीदने की कोशिश की हो। लेकिन यह दोधारी तलवार है। आप सेना की वफादारी हमेशा के लिए नहीं खरीद सकते, आप कुछ समय के लिए साथ बने रहने का समझौता भर कर सकते हैं। तानाशाही सरकारों वाले देशों में सेनाओं की पहली प्राथमिकता हमेशा अपना रुतबा और विशेष अधिकार बनाए रखना होती है। इसके लिए जरूरी हुआ तो वह फायदा देने वाले का साथ भी छोड़ सकती है या उसका समर्थन करने से मुकर सकती है। सबसे कट्टर तानाशाही वाले शासनकाल में भी अंतिम ताकत सेना के ही हाथ में होती है।अरमांडो इआनुची की फिल्म 'द डेथ ऑफ स्टालिन' इतिहास को सही दिखाने का दावा नहीं करती मगर फिल्म में दिखाई गई यह बात निश्चित रूप से सच है कि तानाशाह स्टालिन की मौत के बाद उसके मुख्य जासूस लावरेंटी बेरिया के नेतृत्व वाले स्टालिनवादी गुट को सत्ता से हटाने के लिए मार्शल जॉर्जी झुकोव का समर्थन आवश्यक था।

इसी वजह से शेख हसीना प्रकरण के बाद बांग्लादेश के कदमों पर गौर किया जाना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि सेना कितनी ताकतवर हो जाती है कि वह अगली सरकार भी बना देती है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बेहतर परिस्थितियों में भी 2000 के दशक जैसी सरकारों की तरह ही काम करेगी जो 'सामान्य' राजनीति बहाल करने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तक सत्ता में बनी रहीं। इसके बाद जो भी सत्ता संभालेगा, उसके पास यह ताकत हो सकती है कि वह सेना को उसकी बैरकों में वापस भेज दे। इसके बावजूद उन्हें सैन्य नेतृत्व के साथ सहमति बनानी होगी, जिसमें सेना के व्यावसायिक हितों की रक्षा करना भी शामिल है। पाकिस्तान और मिस्र की तरह बांग्लादेश में भी नेताओं ने मध्यम और वरिष्ठ स्तर के सैन्य अधिकारियों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए सेना को असैन्य अर्थव्यवस्था में दखल देने की इजाजत दे दी है। ऐसा करने से शुरू में तो लगता है कि सेना का साथ मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से देश में अस्थिरता बढ़ती है। शेख हसीना इस बात को अब समझ चुकी हैं क्योंकि उन्हें भी सत्ता से हटाया जा चुका है। हम सभी को उम्मीद है कि हालात अच्छे होंगे और यूनुस का भी मानना है कि वह शायद इस लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन, निष्पक्ष होकर देखा जाए तो बांग्लादेश की राजनीति के लक्षण अच्छे नहीं हैं। सेना शायद सत्ता पाने की बहुत इच्छा नहीं रखती हो, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। सेना उस सूरत में भी ऐसा कर सकती है, जब उसे लगे कि कोई दूसरा विकल्प अराजकता और निरंतर अव्यवस्था बढ़ा सकता है या राजनीतिक इस्लामवाद का उभार हो सकता है जैसा मिस्र में अब्दल फतल अल-सीसी के शासन में हुआ। भारत और अमेरिका निस्संदेह इस नाटकीय घटनाक्रम के सबसे आत्मसंतुष्ट पात्र रहे हैं। भारत की पड़ोसी देशों से जुड़ी नीति बहुत अच्छी नहीं रही है जिसके कारण जमीनी या समुद्री सीमा से लगे लगभग सभी पड़ोसी देशों से इसकी दूरी बढ़ी है। किंतु यह पिछले कुछ वर्षों में इस पर विचार करने को भी तैयार नहीं दिखा कि शेख हसीना को बिना शर्त समर्थन उसे अलग-थलग कर रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है, उसके पास पिछले दो वर्षों से ढाका में अमेरिका के एक ऐसे राजदूत रहे हैं जिन्होंने अवामी लीग सरकार का अमेरिका के प्रति अविश्वास ही बढ़ाया है और विपक्ष में जिम्मेदार शासन या उदार मूल्यों के प्रति सम्मान के बीज बोने में भी कोई योगदान नहीं दिया।

ये है दुनिया का सबसे डरावना और वीरान आइलैंड, कभी इस बीमारी से पीड़ितों को बिना इलाज के रखा जाता था यहां

कोढ़ रोग को हमारे समाज में हमेशा से ही हीन भावना से देखा जाता है। इस बीमारी को भगवान का शाप या दंड माना जाता रहा है। समाज में लोग कोल्ड रोगियों से हमेशा दूरी बना कर रहे हैं। सदियों से इस बीमारी से पीड़ित लोगों को समाज से अलग रखा गया है। भारत ही नहीं दुनिया के विदेशों में कुष्ठ रोगियों के लिए कई आश्रम चलते हैं। लेकिन यूरोप के ग्रीस और यूनान जैसे देशों ने अपने यहां के कुष्ठ रोगियों को आम लोगों से दूर रखने के लिए एक आईलैंड ही अलग कर दिया था।

इस आइलैंड का नाम स्पिनालॉन्गा आइलैंड है। ये यूनान के सबसे बड़े क्रीट द्वीप के पास स्थित है। ये भूमध्य सागर में मिराबेलो की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद है। लेकिन आज इस आईलैंड पर कोई नहीं रहता और यह वीरान पड़ा है। यहां पर बेहद कम लोग ही जाते हैं। इस जगह की सबसे पहले वेनिस के राजा ने यहां पर सैनिक अड्डा बनाया था। इसके बाद तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि, साल 1904 में क्रीट के लोगों ने तुर्कों को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद यह आइलैंड को कोढ़ के मरीजों का अड्डा बना दिया गया। साल 1975 में दुनिया को इस कोढ़ आश्रम के बारे में पता चला। इसके बाद यूनानी सरकार की बहुत आलोचना हुई।

जिसके बाद यहां के सभी लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया और इस कुष्ठ रोगी आश्रम को बंद कर दिया गया। इसके बाद से स्पिनालॉनगा आइलैंड वीरान पड़ा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस आईलैंड पर कोढ़ के मरीजों के इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं था। इस द्वीप पर एक ही डॉक्टर आता था, वो भी तब जब किसी मरीज को कोई और बीमारी हो जाती थी। इंद्र को बनाने से पहले ही कुष्ठ रोग का इलाज खोज लिया गया था लेकिन यहां रहने वाले मरीजों का इलाज नहीं होता था।

चार धाम यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने पेश किया शानदार टूर पैकेज, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

गर्मियों की छुट्टी में लो कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में कई लोगों को परिवार के साथ चार धाम की यात्रा करने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों के लिए भारतीय रेलवे चारों धामों की यात्रा के लिए एक खास ऑफर लेकर आई है। बता दें कि यात्रियों के लिए पावन धाम की यात्रा के ऐसे पैकेज भारतीय रेलवे की तरफ से समय-समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। आई जानते हैं आईआरसीटीसी के चार धाम टूर पैकेज के बारे में -

इतने दिनों का होगा टूर पैकेज

भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को चार धाम की यात्रा के लिए एक स्पेशल टूर पैकेज दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यह टूर पैकेज आजादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है। इस पैकेज का नाम Char Dham Yatra E& Nagpur है। आईआरसीटीसी की ओर से जारी किया गया यह खास टूर पैकेज कुल 11 दिनों और 12 रातों का है। इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

इस दिन से शुरू होगी यात्रा और इन जगहों के होंगे दर्शन

रेलवे द्वारा यह चार धाम यात्रा 14 मई 2022 को नागपुर से शुरू होगी। यहां से यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन रवाना होगी। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, गुप्तकाशी, बरकोट, जानकी चट्टी, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी, आदि धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

यात्रा के दौरान यात्रियों को रेलवे की ओर बस और गाड़ी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रतिदिन नाश्ता और डिनर भी मिलेगा और ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था भी करवाई जाएगी।

यात्रियों को देना होगा इतना शुल्क

अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों को 77,600 रुपए देने होंगे। दो लोगों को इस रूप पैकेज के लिए 61,400 चुकाने होंगे। वहीं तीन लोगों को इस पैकेज के लिए 58,900 जमा करने होंगे। बता दें कि बच्चों का अलग से शुल्क पड़ेगा।

मेघालय राज्य की खूबसूरती देखेंगे तो बस देखते ही रह जायेंगे

1972 में असम से अलग होकर भारत के इक्कीसवें राज्य के रूप में नक्शे पर उभरा, अद्भुत नैसर्गिक सुषमा का आलय- मेघालय यानि बादलों का घर। आकाश में बादलों के झुंड, धरती पर चंचल झरने, शांत झीलें और उनमें अपना प्रतिबिम्ब निहारती हरियाली, इन सबके बीच आपकी उपस्थिति आपको अवसर देगी कि आप अपने भाग्य पर गर्व कर सकें। यह राज्य गारो, खासी तथा जयन्तिया जैसी प्राचीन पहाड़ी जनजातियों का मूल निवास स्थान है। इन्हीं लोगों को भारत का प्राचीनतम निवासी माना जाता है।

ब्रिटिश राज के दौरान स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला शहर शिलांग मेघालय की राजधानी है। खासी पहाड़ियों में, समुद्रतल से लगभग 1500 मी. की ऊंचाई पर बसे इस शहर का नाम एक जनजातीय देवता शुलांग के नाम पर पड़ा है। प्यार से मिनी लंदन पुकारे जाने वाले शहर के चप्पे-चप्पे पर अंग्रेजी प्रभाव के निशान खोजे जा सकते हैं।

शिलांग जैसे छोटे शहर में दर्शनीय स्थानों की सूची छोटी नहीं है। शहर के बीचों-बीच स्थित है वार्डलेक। 1893-94 में बनी यह झील पर्यटकों का ही नहीं स्थानीय लोगों का भी प्रिय स्थान है। खूबसूरत बगीचों की हरियाली और झील के बीच में बना लकड़ी का पुल इसकी विशेषता है। इस लकड़ी के पुल पर से आप झील की मछलियों को देख सकते हैं और चाहें तो उन्हें आटे की गोलियां भी खिलाएं। निःसंदेह बच्चों को यह काम बहुत अच्छा लगेगा। झील के पानी में उतरना चाहें तो नौकाविहार कर सकते हैं। खाने-पीने का अच्छा प्रबंध होना इस स्थान को सुविधाजनक भी बना देता है।

यदि आपकी दिलचस्पी पेड़-पोधों में है तो झील के पास स्थित बाटेनिकल गार्डन अवश्य जाएं। वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए यह स्थान बहुत उपयोग साबित होगा। इसके पास ही स्थित डेलिमार वांगखा का तितलियों का सग्रंह भी देखें। दुनिया भर का तितलियों से संबधित जिज्ञासा यहां शांत की जा सकती है।

किताबों में रूचि हो और ज्ञान में वृद्धि चाहें तो विशेष रूप से प्राचीन जीवन शैली से जुड़ी जानकारियों चाहें तो स्टेट सैन्ट्रल लाइब्रेरी जाना उचित होगा। साथ ही आपको अपनी ओर खीचेंगे डांन बास्को तथा आंल सैन्ट चर्च। डांन बास्को चर्च की विशाल इमारत और अनूठा प्रार्थना कक्ष ही इसकी खासियत हैं।

1889 में बना भारत का तीसरा सबसे पुराना गोल्फ कोर्स भी शिलांग में ही है। चीड़ और देवदार के ऊंचे वृक्षों से घिरे इस स्थान की मखमली धास का मजा लेने के लिए आपका गोल्फ में रूचि रखना जरूरी नहीं। अक्सर सूर्यादय और सूर्यास्त के सुन्दर दृश्यों को नजरों में भरनो के लिए भी पर्यटक यहां आते हैं।

खासी जनजाति के मातृ-सत्तात्मक समाज की छाप देंखें यहां के बड़ा बाजार में। इस बाजार को पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। यहां खरीददारी करें हस्तशिल्प की और बांस के बने सामान की। यहां के जीवन को और करीब से जानना हो तो पास ही स्थित पुलिस बाजार भी जाना चाहिए।

शिलांग से लगभग 2 किलोमीटर दूर है एलिफेन्टा फॉल (झरना)। हाथी के आकार के इस प्राकृतिक झरने की सौन्दर्य वृद्धि की है लकड़ी के छोटे-छोटे पुलों ने। इस झरने के नाम के कारण के बारे में लोगों में मतैक्य नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इस जगह के नाम का कारण, कभी यहां हाथियों का पानी पीने आना था जबकि दूसरों के अनुसार, इसका हाथी जैसा आकार। कुछ लोग इसके नामकरण की कथा सुनाते हैं कि किसी अंग्रेज अधिकारी का हाथी रास्ता भटक कर यहां पहुंच गया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई तो यह नाम पड़ा। इसी खींच-तान के बीच एक अन्य कथा यह भी है कि यहां हाथी पानी पीने आते थे। किसी कारण वश यहां एक हाथी की मृत्यू के पश्चात हाथियों ने यहां आना बंद कर दिया। स्थानीय लोग इस मृत हाथी को देखने यहां पहुंचे, यही घटना इस स्थान के नामकरण का कारण है। इसी से यह स्थान लोकप्रिय भी हुआ।

शिलांग और उसके आसपास के क्षेत्र में कई और झरने भी है जैसे मारग्रेट फांल, बिशप फांल, स्वीट फांल आदि।

समुद्र की सतह से लगभग 1960 मी. ऊंचाई पर, शिलांग से करीब 10 किमी. दूर है शिलांग पीक। ऐसा विश्वास है कि जनजातीय देवता शुलांग यहीं निवास करते हैं। यहां के खुले वातावरण और ऊंचाई को ध्यान में रखकर कुछ गर्म कपड़े ले जाना गलत नहीं होगा।

उमियाम झील, गुवाहाटी से शिलांग के बीच का सबसे सुन्दर पड़ाव है। यह स्थान शिलांग से लगभग 17 किमी. दूर है। बड़ा पानी के नाम से प्रसिद्ध यह झील एक बांध के निर्माण के फलस्वरूप अस्तित्व में आई थी। इस झील के पास बने नेहरू उद्यान को भी देखें। यह झील पानी के खेलों के लिए प्रसिद्ध है।

1897 के भयानक भूकंप से धरती पर तराशे गए दर्रे के लिए विख्यात है माफलोग। यहां प्रकृति की सुन्दरता ने भूकंप की भयावहता को ढक दिया है। शिलांग से लगभग 64 किमी दूर है जरकेम। यहां गधंक के झरने हैं। ऐसा विश्वास है कि झरनों के पानी से अनेक बीमारियों का निदान संभव है।

मेघालय की अन्य दो पहाड़ियां हैं गारो और जयन्तिया। गारो पहाड़ियों को जाना जाता है वनस्पतिक और वन्य जीवन की विविधता के लिए। यहां राष्ट्रीय वन्य जीवन उद्यान तथा नाफक झील भी देखें। यहां सिजु गुफाओं में चूने पत्थर की बनी आकृतियों को देखा जा सकता है।

हिलौरे लेती मिन्तदू नदी से घिरी जयन्तिया पहाड़ी शिलांग से लगभग 64 किमी. दूर हैं। जोवाई, जयन्तिया जनजाति का मुख्यालय भी यहीं है। यहां सिन्दाल गांव में अनेक गुफाओं की सैर की जा सकती है की। जयन्तियां राजा तथा विदेशी आक्रमणकारियों के बीच युद्ध के दौरान कभी इनका प्रयोग छिपने के स्थान के रूप में होता था।

लगभग 1300 मी की ऊंचाई पर, शिलांग से 56 किमी. दूर स्थित है चेरापूंजी। एक लंबे समय, इस क्षेत्र को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। यहां रोमांच लें विश्व के चौथे सबसे ऊंचे झरने नहिकालीफाई को देखने का। इसी प्रकार मांसमाई और लम लाबाध की रहस्यमयी गुफाओं की सैर भी यादगार साबित होगी।

वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा तथा लगभग निरन्तर बने रहने वाले इन्द्रधनुषों की भूमि मांसेनरम, चेरापूंजी के पास ही है। वर्षा ऋतु में लगभग अगम्य बन जाने वाला यह स्थान अपने चूने पत्थर के बने विशाल शिवलिंग के लिए खासा लोकप्रिय है। यहां भयावह ऊंचाई लिए बेहत खूबसूरत झरने भी आपको भाएंगे।

जून-जुलाई का समय मेघालय में उत्सवों का समय है। 4 दिनों तक चलने वाला किसानों का उत्सव है वेटडीनक्लामू। इसमें पारम्परिक नृत्य संगीत के साथ-साथ बैलों की लड़ाई का मजा लें। स्थानीय देवता यू शिलांग और पूर्वजों के सम्मान में आयोजित होने वाले नौंग क्रेम नृत्य उत्सव में शामिल होना नहीं भूलें।

अधिक वर्षा वाले दिनों को छोड़ हर मौसम में यहां आया जा सकता है। यहां का जाड़ा कुछ अधिक ठंडा और गर्मियां सुहावनी होती हैं। निश्चय ही यह छोटा-सा राज्य गर्मी से बड़ी राहत दिला सकता है।

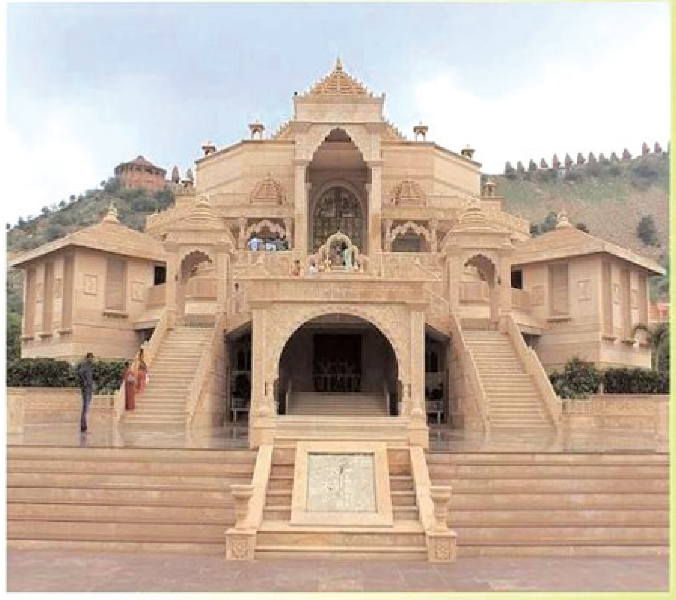

ये हैं अजमेर में घूमने की खूबसूरत जगहें, इन्हें नहीं देखा तो अधूरी है आपकी यात्रा

राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ अजमेर शहर एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यह शहर सूफी संत मोइउद्दिन चिश्ती की दरगाह के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। अजमेर शहर को पहले 'अजयमेरु' के नाम से जाना जाता था। यह शहर अपनी विशिष्ट वास्तुकला और संस्कृति के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। अजमेर में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो देश-विदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। इस शहर में आपको पारंपरिक राजस्थानी रंग-ढंग देखने को मिलते हैं। आज के इस लेख में हम आपको अजमेर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं -

अजमेर शरीफ़

अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस दरगाह में हर धर्म-जाति के लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किमी। पैदल चलकर ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बेटा होने की दुआ माँगने आए थे। आज के समय में देश-विदेश से लोग दरगाह पर आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पुअर होने के बाद चादर चढ़ाते हैं।

आना सागर झील

अजमेर में आप आना सागर झील देख सकते हैं। यह एक बेहद खूबसूरत कृत्रिम झील है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता आणाजी चौहान ने करवाया था। आणाजी से नाम पर ही इस झील का नाम आना सागर पड़ा। इस झील के आसपास की जगह भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ का दौलत बाग देखने में बहुत खूबसूरत है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इस झील में आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं।

पुष्कर सरोवर

अजमेर स्थित पुष्कर झील देशभर में बहुत मशहूर है। यह सरोवर हिन्दू धर्म के लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। भारत के पांच पवित्र सरोवरों में पुष्कर झील भी शामिल है। कुछ विशेष अवसरों पर यहां श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। अजमेर आए पर्यटक पुष्कर सरोवर घूमने जरूर आते हैं। यहां आप ऊंट सवारी का आनंद ले सकते हैं।

अढ़ाई दिन का झोपड़ा

अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1192 में मोहम्मद ग़ोरी के निर्देश पर कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। इस मस्जिद में ढ़ाई दिन का उत्सव चलता है जिसकी वजह से इस मस्जिद को यह नाम दिया गया है। इस मस्जिद के निर्माण में खूबसूरत वास्तुकला का इस्तेमाल देखने को मिलता है। दूर-दूर से लोग इस मस्जिद में मत्था टेकने आते हैं।

तारागढ़ किला

तारागढ़ किला, अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1354 में किया गया था और यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन संरचनाओं में से एक है। यह किला पर्यटकों के लिए राजस्थानी वास्तुकला का एक शानदार और उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है।

सोनी जी की नसियां

अजमेर में स्थित सोनी जी की नसियां एक प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर को समर्पित हैं। सोनी जी की नसियां मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका मुख्य कक्ष है, जिसे स्वर्ण नगरी या सोने के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में जाएं धर्म से जुड़ी सोने की लकड़ी की कई आकृतियां बनी हुई हैं। यह मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और दूर-दूर से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

देशवासियों को मोदी ने दी पहले अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं

नईदिल्ली। आज का दिन भारत और अंतरिक्ष इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन वर्ष 2023 में भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखा था। चंद्रयान 3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता 23 अगस्त के दिन ही मिली थी। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब अंतरिक्ष में इसरो ने उपलब्धि हासिल की थी मगर इससे पहले भी कई मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वैसे चंद्रयान 3 मिशन बेहद खास इसलिए था क्योंकि चांद पर लैंड करने वाला भारत चौथा देश बना है। इसके अलावा दुनिया का वो पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता हासिल कर सका है। इस उप्लब्धि को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी फैसले लिए है और आगे भी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे।

कोलकाता मामले पर अधीर रंजन की सिब्बल से अपील

कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष जबरदस्त तरीके से ममता सरकार पर हमलावर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार का पक्ष रख रहे मशहूर वकील कपिल सिब्बल से खुद को कोलकाता मामले से अलग करने का अनुरोध किया है। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल एक मशहूर वकील हैं। वह भारत की कानूनी दुनिया के भी एक बड़े सितारे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को वापस ले लें या इससे दूर रहें। उन्होंने कहा कि मैं यह बात बंगाल के आम लोगों की भावनाओं और गुस्से को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं। आप अपराधियों का साथ न दें तो बेहतर है क्योंकि आप कभी लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि थे। अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं।

पहले चरण की 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है एनसी

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए गठबंधन करने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित होने के बाद 18 सितंबर को अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए जा रहा है। पहले चरण में 24 सीटों में से 16 कश्मीर और 8 जम्मू क्षेत्र में हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होगा। सूत्रों ने बताया कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 सीटों, कांग्रेस 10 और सीपीआईएम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख के आवास पर अब्दुल्ला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बैठक के बाद यह घोषणा की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में सूचीबद्ध 12 गारंटियों में अनुच्छेद 370 की बहाली, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना और 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को लागू करना शामिल हैं।

5 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। इस बीच, सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत पर हलफनामा दाखिल किया, जबकि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले में उसने एक हफ्ते का समय मांगा है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी।

हरियाणा में आप और जेजेपी का होगा गठबंधन?

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वे हरियाणा में चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। फतेहाबाद में बोलते हुए, आप के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि 1 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन के बारे में कोई चर्चा चल रही है, जबकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने जींद में कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि यह मीडिया है जो इस तरह के गठबंधन के बारे में बात करता रहता है। पाठक ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि जेजेपी के साथ गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं चल रही है।

चुनाव बाद राज्यसभा में एनडीए को मिल सकता है बहुमत

नईदिल्ली। राज्यसभा उपचुनाव में 12 में से 11 सीटें जीतने के लिए तैयार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए उच्च सदन में बहुमत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर और मनोनीत सदस्यों की श्रेणी से अभी भी आठ सीटें खाली हैं। चुनाव वाली 12 सीटों में से कांग्रेस केवल तेलंगाना में एक सीट जीत सकती है, जहां उसने वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी को मैदान में उतारा है। भाजपा नौ सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए के घटक दल एनसीपी और राष्ट्रीय लोक मंच को एक-एक सीट मिल रही है।

वर्तमान में एनडीए के पास 110 सांसदों का समर्थन है, जिसमें छह गैर-गठबंधन वाले मनोनीत सदस्य और हरियाणा से एक निर्दलीय शामिल हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने पर 237 सदस्यों वाले सदन में यह संख्या बढ़कर 121 हो जाएगी, क्योंकि पार्टियों द्वारा मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवारों के निर्वाचित होने की संभावना है। जब सरकार मनोनीत श्रेणी में चार रिक्तियों को भरने का विकल्प चुनती है, तो एनडीए का समर्थन आधार बढ़कर 125 हो सकता है, जो सदन की पूर्ण शक्ति 245 होने पर आवश्यक संख्या से दो अधिक है। आठ मनोनीत सांसदों में से दो भाजपा में शामिल हो गए हैं, जबकि अन्य सरकार का समर्थन करते हैं।

जम्मू-कश्मीर की चार सीटें, जो फरवरी 2021 से

खाली हैं, के लिए चुनाव अक्टूबर में विधानसभा के गठन के बाद कराए जाएंगे। उपचुनावों के साथ, भाजपा के पास 96 सांसद होंगे, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के पास 27 होंगे। तृणमूल कांग्रेस 13 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके बाद आप और डीएमके (10-10) और आरजेडी (5) हैं। विपक्षी दल इंडिया के पास 88 सांसद हैं और सरकार से मुकाबला करने के लिए वह बीजेडी के आठ सांसदों पर भी भरोसा कर सकती है।

वाईएसआर कांग्रेस (11), एआईएडीएमके (4) और बीआरएस (4) गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन सरकार की ओर झुकाव रखते हैं। बीएसपी के पास भी एक सदस्य है, जो हाल ही में विपक्ष के साथ देखा गया है। सत्तारूढ़ भाजपा को राज्यसभा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खासकर एआईएडीएमके के गठबंधन छोड़ने और बीजेडी के कारण, जो संसद के अंदर रणनीतिक समर्थन प्रदान कर रही थी, ओडिशा में चुनावी हार के बाद खुद को विपक्ष की जगह पर रख रही थी। राज्यसभा के दस सांसदों के लोकसभा के लिए चुने जाने और दो - बीआरएस के केशव राव और बीजेडी की ममता मोहंता - के कांग्रेस और भाजपा में शामिल होने से पहले इस्तीफा देने के बाद दर्जन भर सीटों के लिए चुनाव जरूरी हो गए थे। 12 में से, भाजपा के पास सात सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास दो- हरियाणा और राजस्थान- और राजद, बीआरएस और बीजेडी के पास एक-एक सीट थी। हालांकि कांग्रेस ने बीआरएस की कीमत पर तेलंगाना में जीत हासिल की, लेकिन उसने राजस्थान और हरियाणा में अपनी मौजूदा सीटें खो दीं, जहां भाजपा सत्ता में है और अपने उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए उसके पास संख्या है। भाजपा ने बिहार और महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों के साथ एक-एक सीट साझा की। भाजपा ने अपने दो केंद्रीय मंत्रियों जॉर्ज कुरियन और रणवीत बिट्टू को मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव जिता दिया, जबकि कांग्रेस छोड़कर आई किरण चौधरी को हरियाणा से टिकट दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, को असम से टिकट दिया गया।

मोदी ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात

कीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। यह मुलाकात युद्धग्रस्त देश की ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को गले लगाया और उनके कंधे पर हाथ रखा। इस दौरान जेलेंस्की भावुक हो गए, जब दोनों ने मारे गए बच्चों को मर्टीरोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई। जिसमें सभी की नजरें रूस-यूक्रेन युद्ध पर मोदी की स्थिति पर थी।

यह 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा है। इससे एक महीने पहले मोदी ने रूस का दौरा किया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। तब जेलेंस्की ने मोदी की पुतिन से मुलाकात की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री पोलैंड से दस घंटे का सफर करने के बाद कीव पहुंचे और यूक्रेनी अधिकारियों व भारतीय समुदाय से मिले।

उन्होंने एक्स पर लिखा, आज सुबह कीव पहुंचा। भारतीय समुदाय ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे में राजनीति, व्यापार, आर्थिक निवेश, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मानवीय सहायता जैसे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भारत संघर्ष के जल्द समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की अपनी स्थिति को दोहराने की कोशिश करेगा। कीव पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि मैनें और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कीव में मार्टिरोलॉजिस्ट प्रदर्शनी में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष विशेष रूप से बच्चों के लिए विनाशकारी है। इस संघर्ष में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख को सहने की ताकत मिले।

यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन ने हाल ही में रूसी क्षेत्र में आक्रामक सैन्य अभियान चला रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह एक ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर कीव पहुंचे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है।'' मोदी की दो देशों की यात्रा का यह अंतिम चरण है। कीव की यात्रा से लगभग छह सप्ताह पहले मोदी ने रूस की यात्रा की थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संघर्ष समाप्ति के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया था। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ वार्ता के बाद मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष 'गहरी चिंता' का विषय हैं और शांति बहाल करने के लिए 'बातचीत तथा कूटनीति' ही रास्ता है। उन्होंने कहा, ''भारत का दृढ़ता से यह मानना है कि युद्ध के मैदान में किसी समस्या का हल नहीं निकलता।

प्रधानमंत्री के विश्वासघात का जीता-जागता स्मारक है मनरेगा: खरगे

■ **कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप**

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। खरगे ने आरोप लगाया कि मनरेगा की आज जो स्थिति है, वह प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीण भारत से विश्वासघात का जीता जागता स्मारक है। खरगे ने कहा कि 2005 में इसी दिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) लागू किया था।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में

खरगे ने लिखा कि वर्तमान में देश में 13.3 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं जो कम मजदूरी, बेहद कम कार्यदिवस और जॉब कार्ड रद्द होने के बावजूद मनरेगा पर निर्भर हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि प्रौद्योगिकी और आधार का उपयोग करने की आड़ में मोदी सरकार ने सात करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के जॉब कार्ड रद्द कर दिए हैं। इसके चलते ये लोग मनरेगा से कट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि मनरेगा के लिए इस साल का बजट आवंटन कुल बजटीय आवंटन का सिर्फ 1.78 प्रतिशत है, जो 10 साल का सबसे कम है।

खरगे ने तर्क दिया कि मोदी सरकार द्वारा कम आवंटन इस योजना को कृत्रिम रूप से दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली दैनिक मजदूरी अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए, 2014 से उत्तर प्रदेश के लिए दैनिक मजदूरी दर में प्रति वर्ष सिर्फ 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि महंगाई इससे कहीं अधिक बढ़ी है। उन्होंने कहा, आज एक मजदूर औसतन मात्र 213 रुपये प्रतिदिन कमाता है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

खेल
प्रमुख समाचार

नीरज चोपड़ा ने किया सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

लुसाने। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज लुसाने में अपनी लय में नहीं दिखे और लगातार एंडरसन पीटर्स से पीछे रहे। नीरज शुरुआती चार प्रयास में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे और चौथे स्थान पर चल रहे थे, लेकिन पांचवें प्रयास में उन्होंने दम दिखाया और शीर्ष तीन में जगह बनाई। हालांकि, अंतिम प्रयास में नीरज ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 89.49 मीटर का श्रेष्ठ थ्रो किया और वह दूसरे स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने छठे प्रयास में 90.61 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया और विजेता बनकर उभरे। नीरज ने इसी के साथ अगले महीने होने वाले डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

नीरज छठे प्रयास तक अच्छी लय में नहीं दिख रहे थे। उन्होंने 82.10 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की, लेकिन अंत में पेरिस ओलंपिक के अपने 89.45 मीटर के थ्रो को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। नीरज यहां भी 90 मीटर का थ्रो नहीं कर सके जिसे एंडरसन पीटर्स ने संभव किया। जर्मनी के जुलियन वेबर 87.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 82.10 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। हालांकि, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 86.36 मीटर का थ्रो किया, जबकि जर्मनी के जुलियन वेबेर ने पहले प्रयास में 85.07 का थ्रो किया। वहीं, चेक गणराज्य के जाकुब वालदेज पहले प्रयास में फाउल कर बैठे। पहले प्रयास के बाद नीरज चौथे स्थान पर रहे, जबकि एंडरसन ने अपनी बढ़त बनाए रखी। पहला प्रयास समाप्त होने के बाद नीरज दूसरे प्रयास में भी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके और उन्होंने 83.21 मीटर का थ्रो किया जिससे वह तीसरे स्थान पर आ गए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

चौथे दिन हरे निशान में रहे बाजार सेंसेक्स 81,000 के ऊपर

नईदिल्ली। मिलेजुले ग्लोबल संकेतों के चलते 23 अगस्त को शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 33.02 अंकों की बढ़त के साथ 81,086.21 के लेवल पर और 50 शेयरों वाला निफ्टी-50 0.05% यानी 11.65 अंकों की मजबूती के साथ 24,823.15 के लेवल पर बंद हुआ। ऑटो सेक्टर के दम पर आज शेयर बाजार को मामूली बढ़त बनाने में मदद मिली। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान सेंसेक्स 81,231.49 के हाई और 80,883.26 के लो लेवल पर ट्रेड किया था, वहीं, निफ्टी 50 का इंट्रा डे हाई 24,858.40 और लो 24,771.65 का रहा। ओपनिंग प्राइस की बात की जाए तो सेंसेक्स 81,165.65 पर और निफ्टी-50 24,845.40 के लेवल पर ओपन हुआ था। शेयर बाजार में आज ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी-50 पर सिर्फ ऑटो सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर लाल निशान में दिखे।

अनिल अंबानी पर सेबी ने लगाया व्यापारिक प्रतिबंध

नईदिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के हेरफेर के लिए प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या नियामक के साथ पंजीकृत मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में कार्य करने सहित प्रतिभूति बाजार के साथ किसी भी जुड़ाव से पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

पहली छमाही में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार

नईदिल्ली। चालू कैलेंडर साल के पहले छह महीनों (जनवरी-जून) में अमेरिका भारत का शीर्ष कारोबारी साझेदार बनकर उभरा है जबकि देश ने इस अवधि में चीन के साथ 41.6 अरब डॉलर का अपना अधिकतम व्यापार घाटा दर्ज किया है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जनवरी-जून, 2024 के दौरान देश का व्यापारिक निर्यात 5.41 प्रतिशत बढ़कर 230.51 अरब डॉलर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन 41.6 अरब डॉलर के बड़े व्यापार घाटे के साथ सूची में सबसे ऊपर है, क्योंकि चीन को निर्यात 8.5 अरब डॉलर था, जबकि जनवरी-जून 2024 के दौरान आयात 50.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि भारत 239 देशों को उत्पादों का निर्यात करता है और इनमें से 126 देशों ने निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। इन देशों का भारत के कुल निर्यात में 75.3 प्रतिशत हिस्सा है।

इंफोसिस से टैक्स डिमांड वापस लेने की तैयारी में सरकार

नईदिल्ली। भारत सरकार इंफोसिस से 4 अरब डॉलर के अपने पिछले टैक्स डिमांड नोटिस को वापस लेने की तैयारी कर रही है। इस मामले में आईटी इंडस्ट्री और इंफोसिस द्वारा की गई जोरदार खिंचाई और बड़े स्तर पर विरोध के चलते सरकार इस पर फिर से विचार कर रही है। दो सरकारी सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि वित्त मंत्रालय का मानना है कि यह नोटिस भारत की व्यापक टैक्स नीति के विरुद्ध है, और इसमें सेवाओं के निर्यात पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। पिछले महीने टैक्स जांच यूनिट ने इंफोसिस को यह एक्स्ट्रा रकम चुकाने का आदेश दिया था और कहा था कि उसकी विदेशी ब्रांचेज को 2017 से जीएसटी का पेमेंट करना चाहिए। हालांकि, अब वित्त मंत्रालय इस निर्णय में बदलाव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा 9 सितंबर को औपचारिक निर्णय लिया जा सकता है।

चीन खुद एक वैश्विक समस्या, फिर भी दुनियाभर के बाजारों पर दबदबा

शिव शुक्ला

वेनेजुएला के भूतपूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने 2000 के दशक में अपने देश का आर्थिक भविष्य उभरते चीन के ऊपर दांव पर लगा दिया, इससे उसे अरबों डॉलर का निवेश मिला और तेल सौदों के लिए कर्ज भी। शुरुआत में इससे फायदा हुआ। चीन ने जमकर वेनेजुएला के तेल का उपभोग किया और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया। लेकिन 2010 के दशक में तेल की कीमतें गिर गईं और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ चीन की ओर से तेल की मांग भी घट गई। नतीजतन वेनेजुएला के तेल निर्यात का राजस्व 2016 में घटकर 22 अरब डॉलर रह गया। उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। लोग कचरे के ढेर में भोजन तलाशने लगे, अस्पतालों में दवाओं की कमी थी और अपराध बढ़ गए थे। तब से, लगभग 80 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं। चीन ने वेनेजुएला को नए ऋण देने से मना कर दिया, जिससे वहां अधूरी परियोजनाओं का ढेर लग गया।

चीन पर वेनेजुएला की अत्यधिक निर्भरता एक चेतावनी थी, जिसकी दुनिया ने अनदेखी की। चीन के उदय से लाभान्वित दर्जनों अन्य देश अब वित्तीय संकट और ऋण न चुका पाने के जोखिम में फंसे हैं, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था ठहर गई है। फिर भी चीन ऋण राहत देने से इन्कार कर रहा है और संरक्षणवादी गतिविधियों पर दोगुना जोर दे रहा है, जबकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त करने और नई शुरुआत के लिए सुधार करने चाहिए। यह बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था के जादुई गुब्बारे का दूसरा पहलू है।

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया को एक रक्षक की जरूरत थी और चीन ने वह भूमिका निभाई। इसका

सकारात्मक प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया। वर्ष 2008 से 2021 तक चीन ने वैश्विक विकास में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। विकासशील देशों ने खुद को चीन से जोड़ा, और चीन दुनिया के अधिकांश देशों का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। वेनेजुएला की तरह कई देशों ने पाया कि तेजी से बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था उनके वस्तु निर्यात के लिए एक आकर्षक बाजार है, और उन्होंने उसमें भारी निवेश किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सुस्ती का सामना करना पड़ा। चीन ने विभिन्न देशों को दस खरब डॉलर से ज्यादा का ऋण दिया है, जिसका बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों द्वारा बीआरआई (बेल्ट?एंड रोड इनीशिएटिव) के तहत बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचे के लिए है। मगर चीन की तेजी टिकाऊ नहीं थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उद्यमशीलता को दबाया, सुधार का विरोध किया और अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया को उकसाया।

शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद चीन के आर्थिक विकास में काफी कमी आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुश्किल से ही बढ़ रहा है। हालांकि चीन ने लगातार बाहरी स्रोतों के अनुमान से ज्यादा विकास का दावा किया है। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है, जिन्होंने अपने आर्थिक विकास को चीन से जोड़ रखा है। कई देशों द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट आई है।

चीन अपनी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए चीनी निर्माताओं को भारी ऋण और सब्सिडी दे रहा है, जिससे दुनिया भर के बाजार सस्ते उत्पादों से भर गए हैं, वैश्विक वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं और दूसरे देशों के निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बेशक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी के लिए सिर्फ चीन ही जिम्मेदार नहीं है, जो महामारी, युद्ध और व्यापार तनावों से प्रभावित है। लेकिन वह नाजुक समय में हालात को और भी बदतर बना रहा है। चीन?ने विदेशी ऋण में भारी कटौती की है और विकासशील देशों को अपने मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए मजबूर कर रहा है। जांबिया और श्रीलंका को गहरे वित्तीय संकट में धकेलने में चीनी ऋणों का बहुत बड़ा हाथ था। आंशिक रूप से चीनी ऋण की अपारदर्शी प्रकृति के कारण दोनों देशों के संकट और बढ़ गए।

एमओयू पर छिड़ी सियासी जंग

'चुनावी सब्जबाग, एमओयू हुआ ही नहीं': मूणत 'एमओयू का सिर्फ कंसेट दिया': ढेबर

रायपुर. राजधानी में लाइट मेट्रो ट्रेन शुरू करने की महापौर एजाज ढेबर की योजना पर सवाल उठ गया है. पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ किए गए कथित एमओयू को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महापौर ढेबर जिस एमओयू का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का एमओयू एक देश दूसरे देश के साथ तभी कर सकता है, जब कैबिनेट समिति की मंजूरी मिली हो. मूणत ने कहा कि यदि महापौर एजाज ढेबर ने कथित एमओयू पर दस्तखत किया है, तो इसकी भारत में कोई वैधता नहीं है. उन्होंने यह भी कहा है कि ढेबर की यात्रा निजी थी. वह सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे.

दरअसल, बीते दिन 22 अगस्त को यह खबर आई की राजधानी में लाइट मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक सुविधाओं को लेकर रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज़ ढेबर ने मास्को सरकार के साथ रायपुर शहर में लाइट मेट्रो रेल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान हुआ था.

मेयर ढेबर की विदेश यात्रा पूरी तरह व्यक्तिगतः विधायक राजेश मूणत- उन्होंने मेयर ऐजाज ढेबर के विदेश यात्रा के संबंध में कहा किमेयर ढेबर मास्को (रूस) में जिस परिवहन विकास विभाग की बैठक में हिस्सा लेने की बात कह रहे हैं, उसका निमंत्रण मास्को शहर के डिप्टी मेयर ने दिया था, न कि वहां की सरकार ने. मेयर ढेबर की यह यात्रा व्यक्तिगत है, जिसका पूरा खर्च वही उठा रहे हैं. राज्य सरकार से इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है, मेयर ढेबर सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह सरकारी यात्रा भी नहीं है.

आगामी चुनाव के लिए सब्जबाग जमाने की कोशिश कर रहे मेयरः विधायक राजेश मूणत- आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर समेत प्रदेश में जल्दी ही नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मेयर ढेबर ने कथित तौर पर लोगों को यह सब्जबाग दिखाने की कोशिश की है. जो कुछ भी मेयर इस यात्रा में कर रहे हैं, वह पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत क्षमता में किया जा रहा है. इसलिए कोई भी समझौता या एमओयू, जिसे वे हस्ताक्षरित करते हैं, उसे आरएमसी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं माना जा सकता है.

सरकार से इस स्न्ह पर जल्द की जाएगी चर्चाः ऐजाज ढेबर- इस मामले को लेकर महापौर ऐजाज ढेबर ने कहा कि ऐसे स्न्ह सरकार के माध्यम से ही होते है, इस बात की जानकारी मुझे है. उन्होंने कहा मॉस्को के समिट और मेट्रो रेल की जानकारी फरवरी के सामान्य सभा में 15 मिन के भाषण के दौरान पार्षदों को जानकारी दी गई है. इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट में शामिल होकर रायपुर में लाइट मेट्रो रेल के लिए मैंने कंसेंट दिया है और मॉस्को दौरे से लौटकर सरकार से इस स्न्ह पर चर्चा भी जल्द की जाएगी.

वहीं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर ऐजाज ढेबर पर निगम की छवि धूमिल करने और जनता को धोखे में रखने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी है, कि कोई भी बात उन्हें तथ्यात्मक रूप से रखनी चाहिए. अपने निजी यात्रा दौरान की कई कार्यों को आधिकारिक बताना, शहर की जनता के साथ धोखा करने जैसा है.

इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मैं दो बार रायपुर का महापौर रह चुका हूं. यह योजना सैकड़ों करोड़ की है. कोई महापौर दूसरे देश जाकर स्वयं कैसे एमओयूी साइन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर राज्य सरकार की भागीदारी होनी आवश्यक है. निगम एक लोकल गवर्नमेंट है, जो अन्तर्राष्ट्रीय एमओयू नहीं कर सकती ।

महापौर ने रायपुर की जनता के साथ किया भद्दा मजाकःसाव

राजधानी में लाइट मेट्रो ट्रेन शुरू करने के महापौर एजाज ढेबर के एमओयू को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भद्दा मजाक करार दिया है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डिप्टी सीएम साव ने कहा कि शहर के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर की जनता के साथ भद्दा मजाक किया है। जनता को अपमानित किया है और धोखा दिया है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार की अनुमति, एक निजी यात्रा में महापौर ढेबर लाइट मेट्रो के लिए एमओयू कर रहे हैं। पांच साल, जिन्होंने सड़क नहीं बनाई, विकास के एक काम नहीं किया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख महापौर ढेबर रायपुर की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से बड़ा अपराध है। राज्य सरकार की अनुमति से कोई यात्रा अधिकृत होती है। केंद्र और राज्य के एजेंसियों की अनुमति होती है, इस एमओयू में कुछ भी नहीं है,जनता महापौर एजाज ढेबर को माफ नहीं करेगी। बता दें कि बीते दिन 22 अगस्त को यह खबर आई की राजधानी में लाइट मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक सुविधाओं को लेकर रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर ने मास्को सरकार के साथ रायपुर शहर में लाइट मेट्रो रेल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान हुआ था।

गुरु परंपरा पर बोलकर बुरी तरह से फंसे पूर्व मंत्री डहरिया

रायपुर. गुरु परंपरा पर बयान देकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं. उनके बयान के बाद बाबा गुरु घासीदास के वंशज भड़क उठे हैं. आलम ये है कि उनके बयान के बाद उन्ही के पार्टी के पूर्व मंत्री गुरू रुद्र ने उन पर सवाल उठा दिया है. पूर्व मंत्री गुरू रुद्र ने कहा कि शिव कुमार डहरिया को गुरु परंपरा की समझ नहीं है. इसके अलावा बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि डहरिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं.

बता दें कि आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए गुरु बालदास पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास सतनामी समाज के असली गुरु हैं. सभी बाबा गुरु घासीदास को मानते हैं. बाबा जी के वंश में पैदा होने से कोई गुरु नहीं हो जाते. समाज के 80 प्रतिशत लोग गुरु प्रथा को बंद करना चाहते हैं. सतनामी समाज एक है. ये गुरु अवसरवादी लोग हैं, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की ओर थे, अब भाजपा में चले गए. उन्होंने कहा आगे कहा कि जो गुरु भाजपा में चले गए हैं, उनकी स्वीकारता अब नहीं रह गई है. पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के इस बयान के बाद बाबा गुरु घासीदास के वंशज भड़क गए हैं.

आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि शिव कुमार डहरिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं. उन्होंने 5 साल मंत्री रहते सतनामी समाज पर अत्याचार किया. डहरिया को मानसिक इलाज की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ भी मिलेगा. पूर्व मंत्री डहरिया के बयान के बाद अब उन्ही के पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं. पूर्व गुरू रुद्र ने कहा कि शिव कुमार डहरिया को गुरु परंपरा की समझ ही नहीं है. उन्हें (डहरिया) को इस टाइप की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए. सभी समाज के धर्म गुरु होते हैं. सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज है. फिलहाल पूर्व मंत्री डहरिया के इस बयान ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. अब अपने बयान पर पूर्व मंत्री डहरिया कायम रहते हैं या नहीं ये देखने वाली बात है.

कौंदकेरा में हो रही नई किस्म के धान की खेती, कैंसर रोग में भी उपयोगी

महासमुंद. आप ने धान के कई किस्म देखे होंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते होगे पर आज हम एक ऐसे धान के किस्म से आपको रुबरु करा रहे हैं, जिसे संजीवनी धान कहते हैं. इस संजीवनी धान की खासियत है कि इसके सेवन करने से मानव के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही कैंसर जैसी बीमारियों के रोकथाम में भी उपयोगी है. जहां कृषि वैज्ञानिक इसे किसानों के लिए काफी उपयोगी बताते हुए किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक मान रहे हैं, वहीं इस संजीवनी धान को लगाने वाला किसान भी इस धान की विशेषता बताते नहीं थक रहे हैं. इंदिरा गांधी विश्व विद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे धान की प्रजाति की खोज की है, जिसे खाने से मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के साथ कैंसर जैसी बीमारियों के रोकथाम में भी काफी सहायक साबित होगी. हम बात कर रहे संजीवनी धान की. महासमुंद मुख्यालय के समीप ग्राम कौंदकेरा के खेत में ये संजीवनी धान लहलहा रही है. कृषि वैज्ञानिक डॉ. दीपक शर्मा ने बताया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक नई किस्म के धान की खोज की है, जिसे संजीवनी धान के नाम से जानते हैं. इस किस्म के धान में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण है. इस धान के चावल के सेवन से विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है. ये एक सुगंधित किस्म का धान है, जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट , एंटी कैंसर के गुण हैं. इससे किसान स्वस्थ तो होगा ही साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

एक एकड़ में 15 से 20 क्विंटल उत्पादन की उम्मीद- महासमुंद मुख्यालय के समीप ग्राम कौंदकेरा के खेत में ये संजीवनी धान लहलहा रही है. प्रयोगात्मक तौर पर इसे अंचल के प्रगतिशील किसान योगेश्वर चन्द्राकर ने मात्र एक एकड़ में लगाई है. वे प्राकृतिक तरीके से इसका उत्पादन ले रहे हैं. किसान योगेश्वर ने बताया कि जिले में इसका पहला प्रयोग है. आज इसकी लम्बाई 3 फीट के करीब है. वे गोबर, पत्तों से बनी खाद का उपयोग कर इसका उत्पादन ले रहे हैं.

माता कौशल्या संग तीजा त्यौहार में राजेश्री प्रथम आरती में सम्मिलित होंगे

रायपुर। चित्रोत्पला लोक कला परिषद और। नगर पंचायत चंदखुरी जिला रायपुर के ग्रामवासियों के संयुक्त प्रयास से दिनांक 2 सितंबर से 7 सितंबर 2024 तक, भगवान श्री राम के ननिहाल अर्थात माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी में आयोजित किया जा रहे माता कौशल्या संग तीजा तिहार कार्यक्रम के पहले दिन अर्थात माता कौशल्या की मूर्ति के स्थापना के समय मंगलवार दिनांक 3 सितंबर को पहली आरती के अवसर पर दूधाधारी मठ के प्रधान राजेश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी उपस्थित रहेंगे और पहली आरती उनके द्वारा की जाएगी।

आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के व्यवस्था के संबंध में जोरशोर से कार्य शुरू कर दिए गए हैं और लोगों को निमंत्रण देने का काम भी आरंभ किया जा चुका है। आज इसी क्रम में अशोक तिवारी, राकेश तिवारी और डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर ने दूधाधारी मठ जाकर राजेश्री महंत जी को निमंत्रण पत्र भेंट किया तथा उनसे 3 सितंबर की आरती में पधारने हेतु

निवेदन किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। आयोजकों ने बताया कि इस छह दिवसीय आयोजन में प्रत्येक दिन कोई विशिष्ट अतिथि आरती के समय उपस्थित रहेंगे।इन सभी दिनों में अलग-अलग धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां तो होगी ही साथ ही प्रसाद में केवल ठेठरी खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही लोगों को वितरित किए जाएंगे। मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी को अयोध्या से लाकर सुप्रसिद्ध मूर्तिकार पीरु राम जी को सौंप दिया गया है।मूर्ति निर्माण लगभग पूरा हो गया है। 2 तारीख को उसकी चंदखुरी में स्थापना की जाएगी, तब से लेकर 7 सितंबर तक नियमित पूजा अर्चना और आरती की जाएगी ।वरिष्ठ कलाकार राकेश तिवारी ने आयोजन के लिए विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी में माता कौशल्या की आरती तैयार कर रिकॉर्ड की है और उनकी सेवा में कुछ छत्तीसगढ़ी में भजन भी तैयार किए हैं ।आयोजन का यह दूसरा वर्ष है और यह कोशिश की जा रही है इस वर्ष का आयोजन पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा सफल हो सके।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने बनी कमेटी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं. वन मंत्री केदार कश्यप और खेल मंत्री टंक राम वर्मा समेत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी को सदस्य, सचिव बनाए गए हैं. इसका आदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जारी किया है. बता दें कि 2015 से उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी नहीं मिली है. पिछले 9 साल से ये खिलाड़ी नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, खेल मंत्री, और खेल विभाग के चक्कर लगा रहे हैं. अब इसके लिए कमेटी गठित की गई है. सीएम हाउस में कमेटी की बैठक के बाद खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी.

राजिम पुन्नी मेला का नाम फिर बदला

रायपुर। राजिम में पुन्नी मेला का नाम फिर बदल दिया गया है। राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया था। संशोधन विधेयक राज्यपाल रमेन डेका ने मंजूरी दे दी है। बदले हुए नाम का गजट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब मेले को राजिम कुंभ (कल्प) को नाम दिया गया है। बता दें कि राजिम में लगने वाले मेले का नाम रमन सरकार में राजिम कुंभ मेला हुआ करता था, जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजिम पुन्नी मेला कर दिया था। वर्तमान सरकार ने फिर इस मेला का नाम बदलने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया था, जो पारित किया गया था। अब इसे राज्यपाल रमेन डेका ने मंजूरी दे दी है। राजिम पुन्नी मेला को अब राजिम कुंभ (कल्प) मेला नाम से जाना जाएगा। सरकारी कामकाज में इसे अब कुंभ (कल्प) मेला नाम से प्रतिस्थापित किया गया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

तीन फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है. ये कॉलेज हैं ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सेजबहार रायपुर, नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओल्ड धमतरी रोड, रायपुर और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर है. इन कॉलेजों के द्वारा फीस निर्धारित न किये जाने और संबंधित विभाग के सचिव और संचालक को इस संबंध में समुचित कार्रवाई के लिए लिखे जाने का निर्णय लिया गया है. तीनों डी. फार्मेसी कॉलेजों के निरीक्षण के दौरान प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने पाया कि इन्होंने पूरी सुविधाएं जुटाए बिना कॉलेज प्रारंभ कर दिया. कॉलेजों में न ही पुस्तकालय और प्रयोगशाला है और न ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ वहां मिले. इसी आधार पर समिति ने कार्रवाई का निर्णय लिया है. यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि फीस विनियामक समिति के पास फीस निर्धारण के लिये आवेदन देने के पूर्व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, संबंधित विश्वविद्यालय और संबंधित संचालक से भी अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए.

भारत सरकार ने साक्षी को दिया अवार्ड

गरियाबंद। अंतरिक्ष दिवस पर चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में गरियाबंद जिले के पांडुका में पढ़ने वाली साक्षी बतौर बालिका वैज्ञानिक सम्मानित हुई. यंग साइंटिस्ट प्रतियोगिता में साक्षी ने नवाचार मॉडल के तहत वाई फाई से कई गुना तेज चलने वाला लाई फाई का मॉडल बनाया था. चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत सरकार ने 23 अगस्त को चेन्नई में यंग साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड सेलिब्रेशन का आयोजन किया, जिसमें लाई फाई का मॉडल बनाकर सबको चौंकाने वाली साक्षी जायसवाल भी सम्मानित हुई. चेन्नई में पहली बार आयोजित स्पेश-डे पर अतिथि के रूप में आए रशिया और कजाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री एडिन एइम्बेटोव, सर्गेई कोर्साकोव एवं स्पेस इंडिया के प्रमुख डॉ. केसन ने साक्षी को सम्मानित कर प्रमाण पत्र भी भेंट किया. इस प्रमाण पत्र के साथ साक्षी को अब बाल वैज्ञानिक की उपाधि भी मिल गई है. इस आयोजन में विदेशों से आए कई नामी वैज्ञानिक भी मौजूद रहे. विगत 6 माह से यंग साइटिस्ट इंडिया का ऑनलाइन प्रतियोगिता जारी था. इसमें कई राउंड तक मॉडल की प्रस्तुति किया जाना था. जिले के नवोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्रा साक्षी ने भी अपने स्कूल में नवाचार प्रणाली के तहत कई मॉडल बनाया हुआ था.

राजधानी में जल्द लगेंगे फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन

रायपुर। राजधानी के 10 पार्किंग क्षेत्रों में फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसमें ई वाहन चालकों को सुविधा होगी। चार्जिंग स्टेशन टाटा और एथर पॉवर कंपनी की सहभागिता से लगाए जाएंगे। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने कार्यपालन अभियंता इमरान खान के साथ प्रस्तावित फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थल का निरीक्षण किया। यहां पीपीपी मोड पर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की सहभागिता से फास्ट ईव्ही चार्जिंग स्टेशन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। बता दें कि अभी राजधानी के 4 स्थानों, नगर निगम मुख्यालय भवन पार्किंग स्थल, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाठागांव, कलेक्टोरेट के सामने मल्टीलेवल पार्किंग, जयस्तंभ चौक के समीप पुराना बस स्टैंड मल्टीलेवल पार्किंग में फास्ट 4 व्हीलर ईवी चार्जिंग स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता इमरान खान ने बताया कि अप्रैल में 4 ईवी चार्जिंग स्टेशन में 378.83 यूनिट बिजली खपत हुई है। मई में बिजली खपत 701.24 यूनिट और जून में 1050.10 यूनिट हुई है। इस तरह जुलाई में 1369 यूनिट बिजली खपत हुई है। 4 माह में कुल 3499.17 यूनिट बिजली खपत हुई है, प्रति यूनिट 10.50 पैसे की दर पर नगर पालिक निगम को इससे आय प्राप्त हुई है।

पं. रविशंकर शुक्ल विवि में दो दिवसीय बैगानी भाषा सम्मेलन का शुभारम्भ

माँ, मातृभूमि औऱ मातृभाषा सदा वंदनीय - प्रो. आलोक चक्रवाल

रायपुर। साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय बैगानी भाषा सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ द्य इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल, कुलगुरु गुरुघासीदास विश्वविद्यालय उपस्थित थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष डॉ. माधव कौशिक तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर उपस्थित रहे द्य साहित्य अकादेमी के सचिव के.श्रीनिवाराव ने कहा कि साहित्य अकादेमी का उद्देश्य रहा है की विलुप्त हो रही बोलियों, भाषाओं तथा साहित्य को संरक्षित किया जाए औऱ साहित्य को सहेजा जाए इस दिशा में साहित्य अकादमी सफल भी हुई है,लेकिन भाषा एवं संस्कृति को बचाये रखना औऱ

अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। अतिथि उद्बोधन में पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे प्रख्यात बैगानी विशेषज्ञ ने कहा जब बैगानी साहित्य मौखिक, वाचीक परंपरा पर आधारित था, लेकिन खुशी की बात है कि वर्तमान में कुछ युवा बैगानी साहित्यकार मार्गदर्शन लेते हुए इस साधना, लेखन आदि में निरंतर संलग्न हैं। लोक साहित्यविद महेंद्र कुमार ने बैगानी लोक साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भी बैगानी साहित्य की विषय वस्तु प्रकृति चित्रण पर ही आधारित है।

जिसमें अपनी संस्कृति की झलक मिलती है,जो इसे अपने आप में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर अलोक कुमार चक्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि माता ,मातृभूमि और मातृभाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिऐ। इनका स्थान जीवन में सर्वोच्च है। भाषा हमें हमारे संस्कृति व संस्कारों से जोड़ती है जिससे हमारे अंदर आत्मसम्मान व संस्कार को एक नई दिशा प्राप्त होती है द्य प्रत्येक मानव के जीवन में भाषा व संस्कृति का अपना एक विशिष्ट महत्व है जो की आदिम जातियों की इस भाषा में भी देखने को मिलता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सच्चिदानंद शुक्ल कुलपति पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने कहा कि वर्तमान में बैगा जनजाति ही प्रकृति पूजक है जो अपने समृद्ध विरासत को आज भी सहेज कर संस्कृति के संरक्षण में लगा हुआ है द्य इस जनजाति के पास बहुमूल्य औषधि ज्ञान है जिसके कारण वह सभ्यता के विकास से दूर रहकर के भी अपने स्वास्थ्य को श्रेष्ठ बनाए रखे हुए हैं।

विनोद शुक्ल को मिला साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान, महत्तर सदस्यता से किया गया विभूषित

रायपुर। देश के शीर्ष साहित्यकार, रायपुर के रहने वाले विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी ने शुक्रवार को अपने सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्यता से विभूषित किया. साहित्य अकादमी ने रायपुर में उनके घर में एक संक्षिप्त आयोजन में उन्हें महत्तर सदस्यता प्रदान की. भारत में साहित्य अकादमी का यह सबसे बड़ा सम्मान है.

इस अवसर पर साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने प्रशस्ति पाठ करते हुए कहा कि विनोद कुमार शुक्ल, कविता और गल्प का अद्भुत संयोग रचने वाले सर्जक हैं. यह संयोग कुछ ऐसा होता है कि विधाओं की सीमा का अतिव्यापन-सा हो जाता है.

प्रथमतः कलावादी प्रत्ययों से संसाधित जान पड़ने वाली रचना में गहरे प्रवेश करने पर पता चलता है कि रचनाकार ने अमूर्तन को स्थानीयताओं से मूर्त और प्रयोजनीय बना दिया है. अपरिग्रह का अभ्यासी यह रचनाकार अभिव्यक्ति कला और शब्द-शक्तियों का ऐसा अपूर्व अन्वेषण करता है कि रचना रहस्य-लीला-सी लगने लगती है. किसी स्मृति के आख्यान-सी मृदुल और झिलमिल, जिसमें एक विलक्षण प्रशांति का सुख है. उन्होंने कहा कि इस अर्थ में विनोद कुमार शुक्ल बिलकुल अपने-से रचनाकार हैं, जिनके मूल्यांकन के लिए कला प्रतिमानों को अपने अभिप्राय के लिए शंकित होना पड़ता है और इसलिए नए कला मापदंडों की आवश्यकता महसूस होती है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.